



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]
No. 33]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 1997/फाल्गुन 9, 1918
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 1997/PHALGUNA 9, 1918

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य अनुभाग)

(बजट अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1997

फ्र. सं. 15(1)-बीडी/97:—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

बजट

1997-98

वित्त मंत्री

श्री पी. चिदम्बरम

का

भाषण

28 फरवरी, 1997

भाग 'क'

महोदय,

मैं वर्ष 1997-98 का बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ।

प्रस्तावना

2. प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा की अध्यक्षता में सरकार ने आज 9 महीने पूरे कर लिए हैं। जब मैं 22 जुलाई, 1996 को इस सदन के समक्ष उपस्थित हुआ था तब इस सदन ने मेरे प्रस्तावों पर विस्मय,

उत्सुकता तथा संशय की मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आखिरकार, मैं केन्द्र में सच्चे अर्थ में पहली मिली-जुली सरकार का वित्त मंत्री था। मैं एक ऐसी स्वीकृत क्षेत्रीय पार्टी का पहला वित्त मंत्री भी था जिसका अपना राष्ट्रीय दृष्टिकोण है।

3. माननीय सदस्य कुछ समय के लिए मेरा साथ दें ताकि मैं कुछ क्षणों तक मई 1996 के उन महत्वपूर्ण दिनों पर प्रकाश डाल सकूँ। एक राष्ट्रीय पार्टी ने यह मान लिया था कि उसने सरकार बनाने का अपना दावा खो दिया है। दूसरी पार्टी ने इसके लिए कोशिश की लेकिन वह भी विफल रही। इसी स्थिति में अपेक्षाकृत व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य वाली कुछ पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन किया। इन पार्टियों ने, जिन्हें पहले से ही नगण्य आधार वाला माना जाता था, यह दिखा दिया है कि अवसर मिलने पर वे केवल राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि केन्द्र में भी सरकार बना सकती हैं। एक वास्तविक सहकारी संघ की राज व्यवस्था के आदर्श से अनुप्राणित होकर मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय नीतियां बनाने के लिए पहले से कहीं अधिक बार अन्तर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा विशेष सम्मेलनों में भाग लिया। भारत की स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में संयुक्त मोर्चा द्वारा सरकार के गठन और राष्ट्रीय आम राय से निर्णय लेने के हमारे प्रयासों से भारतीय लोकतंत्र सुदृढ़ एवं मजबूत हुआ है।

4. माननीय सदस्य यह देखेंगे कि मेरे पहले बजट और वर्तमान बजट में एक ठोस निरन्तरता कायम है। बजट का आधार न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। पिछले आठ महीनों के अनुभव ने इस कार्यक्रम की प्रचुर क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर ध्यान आकर्षित करते हुए मेरे पहले बजट में सात मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया था। इन उद्देश्यों में संवृद्धि, बुनियादी न्यूनतम सेवाएं, रोजगार, वृहत आर्थिक स्थिरता, निवेश (विशेषकर आधारभूत संरचना में), मानव विकास तथा व्यवहार्य भुगतान संतुलन जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल थे। मेरा यह विश्वास है कि ये उद्देश्य आज भी उतने ही वैध हैं जितने कि वे आठ महीने पहले थे।

जुलाई, 1996 बजट के वायदे

5. पिछली बार मैंने नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में चालीस से भी अधिक विशेष वायदे किए थे। मैंने ध्यानपूर्वक स्थिति का जायजा लिया है और माननीय सदस्यों को यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि मैंने एक वायदे को छोड़कर इन सभी वायदों को पूरा किया है, जिनका मैं इस समय जिक्र करूँगा। अधिक महत्वपूर्ण वायदों को ध्यान में रखकर मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमने,

- * सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों को 2466 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की;
- * ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ)-II के लिए 2500 करोड़ रुपए की वित्त-व्यवस्था की;
- * विदेशी इक्विटी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन के पात्र उद्योगों की सूची का विस्तार किया;
- * विनिवेश आयोग और टैरिफ आयोग की स्थापना की;
- * जीवन सुरक्षा तथा जन आरोग्य बीमा योजनाएं शुरू कीं; और
- * त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया।

6. जिस वचन को मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ वह है व्यय प्रबंध और सुधार आयोग की स्थापना करना। मैं इसमें इसलिए विफल रहा कि मुझे जिस 'क' टीम का सहयोग चाहिए था उसके स्थान पर मुझे 'ख' टीम का सहयोग मिला जिससे मैं संतुष्ट नहीं था। 'क' टीम के प्रमुख सदस्य इस सदन में और राज्य सभा में मौजूद हैं और वे अभी भी मुझसे बच रहे हैं। मेरा प्रयास जारी रहेगा। मैंने बजट के अन्दर व्यय को नियंत्रित रखने के अपने संकल्प को नहीं छोड़ा है और मैंने इसमें पर्याप्त सफलता प्राप्त की है।

वर्तमान आर्थिक स्थिति

7. कुछ दिन पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण, 1996-97 प्रस्तुत किया गया था। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति का विस्तृत एवं संतुलित लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः अभी भी बहुत कुछ किया जाना है लेकिन ऐसा भी बहुत कुछ है जिस पर गर्व किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था की असाधारण विशेषता यह है कि सकल घरेलू उत्पाद में पिछले तीन वर्षों के दौरान 7 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हो रही है। मैं उन किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों तथा सेवा-कर्ताओं का अभिवादन करता हूँ जिन्होंने इसे संभव बनाया है।

8. 1996-97 में हमारे आर्थिक निष्पादन की सुस्पष्ट विशेषताओं में ये शामिल हैं -

- * 6.8 प्रतिशत पर सतत उच्च आर्थिक वृद्धि,
- * 1995-96 में 0.1 प्रतिशत की निराशाजनक कमी के उपरान्त कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि का 3.7 प्रतिशत तक पर्याप्त सुधार;
- * खाद्यान्न उत्पादन में 191 मिलियन टन तक की तीव्र वृद्धि;
- * विनिर्माण क्षेत्र की 10.6 प्रतिशत पर वृद्धि; और
- * 27 फरवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में 17.0 बिलियन अमरीकी डालर से 19.5 बिलियन अमरीकी डालर का पर्याप्त संचय।

9. यदि मैं कमजोर क्षेत्रों के बारे में न बताऊँ तो मैं न तो अपने प्रति और न ही देश के प्रति खरा उतरूँगा। गंभीर चिन्ता के दो क्षेत्र हैं, देशी कच्चे तेल के उत्पादन में तीव्र कमी तथा विद्युत क्षेत्र का मन्द निष्पादन। चिन्ता के अन्य विषयों में निर्यातों की वृद्धि में कमी, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि तथा अव्यवस्थित पूँजी बाजार शामिल हैं। सरकार ने पिछले तीन महीनों में कुछ दूरगामी पहल शुरू करके इन चिन्ताओं पर ध्यान दिया है। मैंने इस बजट में भी इसके लिए नए प्रस्ताव रखे हैं।

10. वृहत आर्थिक प्रबंध में अनिवार्यतः विभिन्न उद्देश्यों तथा धारणाओं के मध्य संतुलन कायम करना होता है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, 1995-96 में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि तेजी से घटकर 13.2 प्रतिशत हो गई थी। हालांकि इससे मुद्रास्फीति को रोकने में मदद मिली, लेकिन इस कारण वास्तविक व्याज दरों में वृद्धि, नकदी की उपलब्धता में व्यापक कमी तथा निवेश प्रस्तावों में भी कमी हुई। जून, 1996 से, सुधारात्मक कार्रवाई की गई है जिससे मुद्रा की उपलब्धता सुलभ हो गई है तथा व्याज दरों में गिरावट आई है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लंबी अवधि से नहीं की गई वृद्धि और पिछले मौसम में मुख्यतया गेहूँ के अपेक्षाकृत कम उत्पादन तथा कम खरीद के कारण उत्पन्न होने वाली आपूर्ति की समस्याओं से कीमत स्तर पर दबाव पड़ा है। सरकार ने कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं। खरीफ के मौसम में धान का उत्पादन और खरीद संतोषजनक रहे हैं और हमारे पास चावल का

पर्याप्त भंडार है। रबी के गेहूँ की फसल भी काफी आशाजनक है और अधिक से अधिक खरीद के लिए उपाय किए जाएंगे। इसके साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यदि आवश्यकता हुई तो कीमतों पर पड़ने वाले दबाव का मुकाबला करने के लिए सरकार गेहूँ तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात करने से नहीं हिचकिचाएगी। कीमतों में स्थिरता बनाए रखना इस सरकार की कार्यसूची में सर्वोपरि है।

11. आपूर्ति के लिए प्रबंध के अलावा हमें ऐसी विवेकपूर्ण राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियाँ अपनानी हैं जो कीमतों में स्थिरता लाएंगी। वर्ष 1997-98 के लिए, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक राजकोषीय घाटे में और कमी लाने, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को 16 प्रतिशत के भीतर नियंत्रित रखने तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए उदार आयात नीति अपनाने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। हमारा लक्ष्य मुद्रास्फीतिकारी संभावनाओं को समाप्त करना और मुद्रास्फीति की दर को मौजूदा स्तर से कम करना है।

निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम

12. निर्धनता के विरुद्ध हमारा संघर्ष जनाधिकारवाद का कोई खेल नहीं है। यह निचले स्तर का युद्ध है। मैं विश्वास करता हूँ कि यह ऐसा युद्ध है जिसमें हम सभी को निर्धनों के पक्ष में रहना होगा। वे लोग निर्धन हैं, जिनके पास भूमि अथवा जल या शिक्षा अथवा अवसर नहीं होते हैं। इसलिए हमारा कार्यक्रम निर्धनों की परेशानियों और कठिनाइयों से संबंधित है।

- * प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्यक्रम मूल न्यूनतम सेवा योजना है। चालू वर्ष के 2466 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में, 1997-98 के लिए मैं इस का क्रम के लिए 3300 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इस राशि में से 330 करोड़ रुपये गंदी बस्तियों के विकास के लिए होगा।
- * त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए प्रावधान की राशि 900 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1997-98 में 1300 करोड़ रुपये की जा रही है।
- * गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य किसानों की सहायता करना है जिसमें वे आर्थिक सहायता, रख-रखाव सहायता तथा ऋण संबंधी व्यवस्था के माध्यम से भूमिगत जल और भूतल जल के लिए योजनाएं शुरू कर सकें। इसके लिए, 1997-98 में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जा रहा है।
- * जिन जिलों में विशेष रूप से महिला साक्षरता दर बहुत कम है, उन क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना हेतु, प्रधानमंत्री 15 अगस्त, 1997 को कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना नामक कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। इसके लिए मैंने शिक्षा विभाग के लिए 1997-98 के लिए 250 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, नेहरु रोजगार योजना जैसी विभिन्न लक्ष्यों वाली स्व-रोजगार संबंधी सभी मौजूदा स्कीमों को पुनः युक्तिसंगत बनाया जाएगा जिससे एक मिलियन युवाओं के लिए कुशलता-आधारित प्रशिक्षण,

उद्यम विकास तथा आर्थिक सहायता संबंधी बैंक कर्णों की व्यवस्था की जा सके ताकि वे लघु व्यापार आरंभ कर सकें।

13. हमारी सरकार का यह विश्वास है कि निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम महत्वपूर्ण साधन है। इन कार्यक्रमों के लिए अधिक परिव्यय की व्यवस्था करते हुए उनकी संख्या को युक्तियुक्त बनाना तथा उन्हें अधिक केंद्रित तथा कारगर बनाना आवश्यक है। अब योजना आयोग एक व्यापक कार्य में लगा हुआ है तथा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का संशोधित पोर्टफोलियो 1 अप्रैल, 1997 से कार्यान्वित किया जाएगा।

ग्रामीण ऋण

14. कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की प्राण शक्ति है। न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम के लिए पांच वर्षों के भीतर कृषि तथा कृषि-उद्योगों को मिलने वाला ऋण प्रवाह दुगुना करना आवश्यक है। वर्ष 1996-97, जो इस सरकार का पहला वर्ष है, में अनुमान है कि कृषि को मिलने वाला ऋण प्रवाह लगभग 22,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 28,600 करोड़ रुपए हो जाएगा जो कि 6,600 करोड़ रुपए की अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाता है।

15. माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) लोकप्रिय और सफल सिद्ध हुई है। आर.आई.डी.एफ.-I के अन्तर्गत 4,530 परियोजनाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। मार्च 1997 तक लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि का संचितरण किया जाएगा। आर.आई.डी.एफ.-II के अन्तर्गत 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की 8387 परियोजनाओं को मंजूर किया गया है। आर.आई.डी.एफ.-III 1997-98 में शुरू की जाएगी तथा इसके लिए 2,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इन निधियों का सर्वोत्तम उपयोग करते रहें।

16. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) के पुनःपूजीकरण की नीति अगले वर्ष जारी रहेगी। इस प्रयोजन हेतु मैं 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व और प्रबंध में बैंकों को प्रायोजित करने में अधिक भूमिका अदा करने की अनुमति देने का भी इरादा रखता हूँ।

17. नाबार्ड को और सुदृढ़ किया जा रहा है। नाबार्ड को चालू वर्ष में अतिरिक्त अग्रिम शेयर पूंजी के रूप में 500 करोड़ रुपए - 100 करोड़ रुपए सरकार द्वारा तथा 400 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा - दिए गए हैं। वर्ष 1997-98 में इसी तरह के आवंटन द्वारा शेयर पूंजी में वृद्धि की जाएगी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जैसा मैंने पिछले वर्ष वचन दिया था, 'नाबार्ड' ने इस महीने संयुक्त उपक्रमों के रूप में तीन राज्यों में राज्य-स्तरीय कृषि विकास वित्त संस्थाओं को प्रवर्तित और समामेलित किया है। अगले वर्ष और संस्थाओं को समामेलित किया जाएगा।

कृषि पर नियंत्रण

18. न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम में यह कहा गया था कि कृषि उत्पादों पर सभी नियंत्रणों की

समीक्षा की जाएगी और जहाँ आवश्यक पाया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। केन्द्र सरकार के केवल कुछ ही विनियम हैं तथा कुछ को समाप्त करने की शुरुआत की जा रही है। धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 तथा गिन्निंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्रीज एक्ट, 1925 को निरस्त कर दिया जाएगा। शीतागार आदेश, 1964 के अन्तर्गत लाइसेंस देना, मूल्य नियंत्रण और मांग को समाप्त कर दिया जाएगा। खाद्य तेल तथा खाद्य तेल बीज भंडारण नियंत्रण आदेश, 1977 तथा कपास नियंत्रण आदेश, 1986 का आश्रय केवल सुस्पष्ट आपात-स्थितियों में ही लिया जाएगा। बिनीला निकाले हुए तथा गांठदार कपास, गांठदार कच्चे पटसन तथा पटसन की वस्तुओं के संबंध में देशी भावी सौदे फिर से शुरू किए जाएंगे। एक अन्तर्राष्ट्रीय अरबी तेल भावी सौदा एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वे आगे आएँ और जितना संभव हो उतने नियंत्रणों को हटा लें।

लघु उद्योग

19. जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है, सरकार ने हाल ही में लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) के संयंत्र और मशीनरी के लिए निवेश की उच्चतम सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये तथा छोटी-छोटी इकाइयों के लिए 25 लाख रुपये कर दी है। अब प्रवर्धित लघु उद्योग (एस.एस.आई.) क्षेत्र के सभी खंडों के लिए ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अनुदेश जारी कर रहा है कि लघु उद्योग (एस.एस.आई.) क्षेत्र के लिए सामान्यतया उपलब्ध निधियों में से 40 प्रतिशत संयंत्र और मशीनरी में 5 लाख रुपये तक निवेश करने वाली इकाइयों के लिए, 20 प्रतिशत 5 लाख रुपये और 25 लाख रुपये के बीच ऋण निवेश करने वाली इकाइयों के लिए तथा शेष 40 प्रतिशत अन्य लघु उद्योग इकाइयों के लिए आरक्षित रहेगा।

20. सरकार ने हाल ही में यह भी घोषणा की है कि वह लघु उद्योग क्षेत्र के बारे में आबिद हुसैन समिति की अन्य सिफारिशों की ध्यानपूर्वक जांच करेगी। कृषि वस्तुओं में अपशिष्ट को कम करने, गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुधार करने तथा निर्यातों का संवर्धन करने की दृष्टि से, आरक्षण और अनारक्षण संबंधी सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की है कि इस समय लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित 14 मदों को अनारक्षित कर दिया जाए। तब भी लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए 822 मदें आरक्षित रहेंगी। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अनारक्षित मदों में धान कुटाई, दाल कुटाई, कुङ्कुट पोषण, सिरका, सिंथेटिक सिरप, बिस्कुट, आइसक्रीम, कई प्रकार के आटोमोबाइल पुर्जे तथा लहरियादार कागज तथा गत्ते शामिल हैं। आशा है कि इन व्यवसायों में नए निवेश और उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रवाह होगा।

आवास

21. देश की आवास-व्यवस्था को बढ़ाने में नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 बाधक है। सरकार संसद के इस सत्र में अधिनियम को संशोधित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है।

22. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों हेतु गृह निर्माण करने के लिए इन्दिरा आवास योजना शुरु की गई थी। आवास वित्त कंपनियां ऋण उपलब्ध कराती हैं लेकिन ऐसे ऋणों का अधिकतर भाग शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों को प्राप्त होता है। कुछ ग्रामीण आवास ऋण कार्यक्रम हैं लेकिन वे 10,000 रुपए तक की अल्प राशि का ही ऋण देते हैं। ऐसे किसान के लिए ऋण का वस्तुतः कोई स्रोत नहीं है जो अपनी पूर्ण-स्वामित्व वाली भूमि पर एक साधारण मकान बनाना या अपने पुराने निवास में सुधार करना या वृद्धि करना चाहता है। इस अन्तर को अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) और अन्य बैंकों के साथ परामर्श करके, मैंने एक योजना तैयार की है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक के ऋण सामान्य ब्याज दरों पर दिए जाएंगे बशर्ते कि उधारकर्ता मकान की एक तिहाई कीमत की व्यवस्था करें। एन.एच.बी. से ऐसी योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है जिसमें अन्य संगठनों की भी भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री इस योजना को 15 अगस्त, 1997 को शुरु करेंगे और हमारा लक्ष्य पहले वर्ष में 50,000 ऋण स्वीकृत करने का है।

कर्मचारी भविष्य निधि और उपदान

23. केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि न्यासी मंडल (ई.पी.एफ.) ने कर्मचारी भविष्य निधि स्कीमों को वित्तीय रूप से अधिक आकर्षक बनाने के लिए विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। सरकार ने भी बचतों को बढ़ावा देने की दृष्टि से इस मामले की जांच की है। निम्नलिखित निर्णयों की घोषणा करते हुए मुझे खुशी है:

- * उद्योगों तथा स्थापनाओं में नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए 1 मार्च, 1997 से अंशदान की दर 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी जाएगी।
- * अनुसूचित उद्योगों में जहां अंशदान की दर इस समय 10 प्रतिशत है, नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए यह दर 12 प्रतिशत करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
- * विशेष जमा योजना (एस.डी.एस.) में 20 प्रतिशत वृद्धिकारी भविष्य निधि राशि रखने की अपेक्षा को पहली अप्रैल, 1997 से वापस ले लिया जाएगा और न्यासी मंडल निधियों के इस भाग का अन्य तीन किस्मों की अनुमत्य प्रतिभूतियों में से किसी एक में निवेश करने के लिए स्वतंत्र होगा।

24. 1995 में, केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय उपदान की राशि के बारे में अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी थी। अब मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि यह लाभ उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन शामिल सभी कर्मचारियों को भी दिया जाएगा जिसमें इस प्रयोजन हेतु संशोधन किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र की स्वायत्तता

25 न्यूनतम साझा कार्यक्रम ने यह बचन दिया था कि "संयुक्त मोर्चा सरकार उन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों, जिनकी तुलनीय रूप से श्रेष्ठता होगी, का पता लगाएगी और सार्वभौमिक रूप से महान बनने के अभियान में उनकी सहायता करेगी"। प्रारंभ में नौ अच्छे निष्पादन करने

वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों - नवरत्नों का पता लगाया गया है। ये हैं - आई.ओ.सी., ओ.एन.जी.सी., एच.पी.सी.एल., आई.पी.सी.एल., वी.एस.एन.एल., बी.एच.ई.एल., एस.ए.आई.एल. और एन.टी.पी.सी.। उद्योग मंत्री शीघ्र ही उपायों का एक पैकेज घोषित करेंगे जिससे उन्हें इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। वह सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता के संबंध में एक पूर्ण वस्तुस्थिति भी देंगे।

26. इस बीच सरकार ने लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के बोर्ड को अधिक मौद्रिक शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया है। इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पूँजी व्यय, जिसे सरकार की पूर्व अनुमति के बिना खर्च किया जा सकता है, की मौजूदा सीमा को सीधा दुगुना किया जा रहा है तथा जहाँ सकल राशि 500 करोड़ रुपये से अधिक है, वहाँ यह सीमा 100 करोड़ रुपये होगी।

विनिवेश

27. विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त, 1996 में की गई थी और सुझाव प्रदान करने के लिए आयोग के पास 40 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले भेजे गए थे। आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसने तीन कंपनियों के संबंध में विशिष्ट सिफारिशों की हैं। हम आयोग द्वारा सुझाव दिए गए अनुसार इन कंपनियों में विनिवेश जारी रखना चाहते हैं। जबकि आयोग प्रत्येक महीने और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दूसरे समूह का मामला आयोग को भेजा गया है। जैसा कि आयोग ने अवलोकन किया है "दीर्घावधिक विनिवेश कार्यनीति का सार न केवल बजटीय प्राप्तियों में वृद्धि करना बल्कि अलाभकारी इकाइयों को उनकी दीर्घावधिक व्यवहार्यता और उनमें रोजगार के सतत बने रहने वाले स्तरों को सुनिश्चित करते हुए बजटीय सहायता को कम करना भी होना चाहिए।" सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है और मैं माननीय सदस्यों से विनिवेश के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने की अपील करूँगा।

तेल और गैस

28. पेट्रोलियम उत्पादों के लिए देश की मांग 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, जो घरेलू आपूर्ति की वृद्धि की अपेक्षा अधिक तीव्र है। हम इस वृद्धि को रोक नहीं सकते। साथ ही हमें आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। आपूर्ति बढ़ाने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। भारत में 26 बेसिनों में से मात्र 6, जिनमें तेल और गैस की संभावना है, का पता लगाया गया है और वह भी आंशिक रूप से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री शीघ्र ही नई अन्वेषण लाइसेंसिकरण नीति (एनईएलपी) पर एक विस्तृत बयान देंगे। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

- * तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड सहित कंपनियों को नई अन्वेषण लाइसेंसिकरण नीति (एनईएलपी) के अधीन की गई नई खोजों के लिए तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत अदा की जाएगी;
- * विशिष्ट दरों की मौजूदा प्रणाली की बजाय मूल्यानुसार आधार पर रायल्टी भुगतान निर्धारित किया जाएगा;

- * गहरे जल में अन्वेषण के लिए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के बाद प्रथम सात वर्षों के लिए अपतटीय क्षेत्रों हेतु लागू दर के आधे पर रायल्टी का भुगतान प्रभाय होगा;
- * घरेलू बाजार में कच्चे तेल तथा गैस के विपणन की स्वतंत्रता;
- * उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खण्डों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के बाद सात वर्षों के लिए करावकाश;
- * नई अन्वेषण लाइसेंसिकरण नीति के अधीन पूंजीगत सामग्रियों के आयात पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड के निजी उत्पादन भागीदारी संविदाओं के समान ही शुल्क रियायतें प्राप्त होंगी;
- * नए अन्वेषण खण्डों के लिए तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 के अधीन लगाए गए उपकर को समाप्त किया जाएगा।
- * नए निवेशों को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य देशों के समान ही एक पृथक पेट्रोलियम कर-संहिता बनाई जाएगी।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय तथा विदेशी कंपनियों की प्रतिक्रिया उपायों के इस पैकेज के प्रति सकारात्मक होगी।

29. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त घरेलू शोधन क्षमता सृजित की जा सके, मैं नौवीं योजनावधि के दौरान पूंजीगत सामग्रियों का आयात करने वाली शोधनशालाओं को उर्वरक क्षेत्र के समान ही रियायती शुल्क की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। घरेलू पूंजीगत सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को भी निर्यात का मान्य स्तर प्राप्त होगा।

आधारभूत संरचना

30. आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी संस्थापित की गई है। आयकर अधिनियम की धारा 80इक कतिपय आधारभूत संरचना परियोजनाओं को पांच वर्ष का करावकाश प्रदान करती है। पिछले महीने मैंने घोषणा की थी कि दूरसंचार को आधारभूत संरचना की योग्यता प्राप्त होगी। मैं अब तेल-अन्वेषण और औद्योगिक पार्क को इस श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ।

31. मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता है कि दूरसंचार लाइसेंसों की समनुदेशीयता के परेशान करने वाले प्रश्न को हल कर लिया गया है और दूरसंचार विभाग, ऋणदाता तथा लाइसेंसधारी के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किया जाना प्रस्तावित है।

32. वाणिज्य मंत्री के रूप में, मैंने निर्यात-आयात नीति में यह प्रस्ताव किया था कि तेल, गैस और विद्युत परियोजनाओं को सामग्रियों की आपूर्ति, अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली की कार्यविधि के अंतर्गत की जाती है तो उन्हें 'मान्य निर्यातों' का लाभ दिया जाना चाहिए। वित्त

मंत्री के रूप में इस पूरे प्रस्ताव को स्वीकार करने में मुझे प्रसन्नता हो रही है। इससे संबंधित ब्यौरे अलग से अधिसूचित किए जा रहे हैं।

33. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) अब सड़कों और राजमार्गों संबंधी नई नीति को कार्यान्वित करने के लिए तैयार है। मैं एन.एच.ए.आई. के लिए बजट सहायता बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ जो कि चालू वर्ष की 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था से काफी अधिक है।

विदेशी निवेश

34. विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) भारत में अपना अत्यधिक विश्वास बनाए हुए हैं। भारत में अब विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवल निवेश 7 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक है। इस वर्ष के दौरान मैंने ऐसे निवेशों के लिए अवसरों का विस्तार किया है। मैं भारतीय कंपनियों के अनुरोध पर एक और उपाय करने का प्रस्ताव करता हूँ। विदेशी संस्थागत निवेशकों, अनिवासी भारतीयों तथा अनिवासी भारतीय-विदेशी कंपनी निकायों द्वारा किसी कंपनी में कुल निवेशों की सीमा अभी 24 प्रतिशत है। मैं कंपनियाँ को इस सीमा को इस शर्त के अधीन कि कंपनी का निदेशक मंडल सीमा अनुमोदित करता है और कंपनी की आम सभा इसके लिए एक विशेष संकल्प पारित करती है, बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

35. नए उपक्रमों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उपक्रम पूँजी निधियाँ महत्वपूर्ण साधन हैं। मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन ये निधियाँ किसी एक कंपनी की इक्विटी में अपनी संग्रहित राशि का 5 प्रतिशत तक निवेश कर सकती हैं। यह अनुचित रूप से प्रतिबंधात्मक है। इस सीमा को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है।

पूँजी बाजार

36. 20 मिलियन से भी अधिक भारतीयों ने अपनी बचतों का पूँजी बाजार में निवेश किया है। प्रथम निक्षेपागार की स्थापना भारतीय पूँजी बाजार को विश्व स्तर तक लाने और निवेशकों के हितों का संरक्षण करने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। "सेबी" से और उपायों का सुझाव देने के लिए कहा गया था। नया कंपनी विधेयक बनाने के लिए मेरे द्वारा नियुक्त समिति ने भी मूल्यवान सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर विचार करने के बाद, मैं पाँच सिफारिशों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ :

- * कतिपय शर्तों के अधीन कंपनियों द्वारा शेयरों की पुनः खरीद का सिद्धांत कंपनी अधिनियम में शामिल किया जाएगा।
- * कंपनी अधिनियम की धारा 370 और 372 के उपबंधों को मिला दिया जाएगा और अन्तः निगमित निवेश तथा ऋणों के लिए 60 प्रतिशत की समग्र सीमा रखी जाएगी;

- * प्रतिभूतियों के धारकों के लिए नामांकन सुविधा प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम को संशोधित किया जाएगा;
- * पूंजी बाजार से निधियां जुटाने वाली कंपनियों को ऐसी निधियों के अंत-प्रयोग को प्रकट करते हुए एक वार्षिक विवरण देना होगा; और
- * पूंजी अभिलाभों पर कर लगे बिना, जिससे छूट दी जाएगी, स्टॉक दलालों को उनके व्यापारों को निगमीकृत करने की एक-बार अनुमति दी जाएगी।

37. मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर आर्थिक वृद्धि सुदृढ़ बनी रहे, राजकोषीय घाटा कम किया जाए, ब्याज दरें गिर जाएं और निवेशकों को पुनः आश्वस्त किया जाए कि उनके हित सुरक्षित हैं तो बाजारों की उन्नति होगी।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और काले धन को वैध बनाना

38. शेष विश्व के साथ व्यापार और निवेश के अधिक संयोजन के साथ चूंकि हम अधिक मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए विदेशी मुद्रा लेन-देनों को शासित करने वाले विनियमों को भी आधुनिकीकृत करने की आवश्यकता है। साधारणतया यह माना जाता है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 को पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता और पूंजी खाता लेन-देनों को प्रगामी तौर पर उदारीकृत बनाने के हमारे उद्देश्यों के संगत एक नए कानून द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा इस वर्ष के उत्तरार्ध में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम नामक एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त दल द्वारा शीघ्र ही इस विधेयक का प्रारूपण पूरा कर लेने की आशा है।

39. जबकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम प्रतिस्थापित किया जा रहा है, हम गलत तरीके से प्राप्त धन के वैधीकरण को रोकने के अपने प्रयासों में ढील नहीं देंगे। काले धन को वैध बनाने से निपटने के लिए एक विधेयक तैयार किया जा रहा है और मेरा इसे संसद के इसी सत्र में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

पूंजी खाता परिवर्तनीयता

40. कुछ दिनों पूर्व मैंने पूंजी खाता परिवर्तनीयता का हवाला दिया था। हमें अपने विदेशी मुद्रा अर्जकों पर गर्व है। उन्हें निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा (ई.ई.एफ.सी.) खाते की सुविधा दी गई है। इस समय, इन खातों में कुल राशि 2000 करोड़ रुपए है। मैं निम्नलिखित सुविधाओं की अनुमति देते हुए खाते की व्यापकता में विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूँ -

- * विदेशों में कार्यालय खोलकर और उनके व्यय की पूर्ति करना और
- * भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किए बिना समुद्रपारीय संयुक्त उपक्रम खाते में बाकी शेष राशि से 15 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक निवेश करना।

41. मेरा यह भी विश्वास है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए प्रारंभिक कार्य करने का समय आ गया है। यह एक अभिष्ट लक्ष्य है। यह अत्यधिक संवेदनशीलता का भी विषय है। इसलिए मैं कोई वायदा नहीं करूंगा। फिलहाल मैं भारतीय रिजर्व बैंक से पूंजी खाता

परिवर्तनीयता के लिए रूपरेखा तैयार करने, प्रत्येक धरण पर उपलब्ध किए जाने वाले आर्थिक मानदण्ड निर्धारित करने और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विस्तृत समय-सारणी बनाने के लिए विशेषज्ञ दल नियुक्त करने का अनुरोध कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसे दल की नियुक्ति अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में शामिल होने के हमारे संकल्प के बारे में विश्व को शक्तिशाली संकेत देगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

42. मेरे पिछले बजट को कतिपय क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी-अनुकूल माना गया था। मिथ्या-प्रशंसा का अपना लाभ होता है, और मैं वैज्ञानिक समुदाय के साथ अपनी मित्रता मजबूत करने की इच्छा रखता हूँ। मैं निम्नलिखित पहल करने का प्रस्ताव करता हूँ :

- * वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं तथा साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा अर्जित प्रत्येक अतिरिक्त वाणिज्यिक रूपए को समतुल्य बनाने की स्कीम स्थायी आधार पर जारी रहेगी।
- * देशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण की गति तेज करने हेतु स्थापित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने कृषि, स्वास्थ्य, रसायनों और भेषजों के क्षेत्र में 16 परियोजनाओं का पता लगाया है, जो वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य हैं। वर्ष 1996-97 में मैंने प्रौद्योगिकी विकास निधि को 30 करोड़ रूपए प्रदान किए थे। मैं वर्ष 1997-98 में इस आवंटन को बढ़ाकर 70 करोड़ रूपए करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

43. भविष्य की प्रौद्योगिकी वर्तमान विज्ञान पर आधारित है। मैं चिंतित हूँ कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा के प्रति दिलचस्पी में कमी हो रही है। मेरा यह मत है कि कोई भी यहां तक कि हार्वर्ड से शिक्षा प्राप्त एम.बी.ए. भी, किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है। हमारी स्वतंत्रता की 50वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री "स्वर्णजयंती" फेलोशिप का शुभारंभ करेंगे। 45 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात और प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को विज्ञान में विश्व श्रेणी का स्तर प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए सहायता दी जाएगी। शिक्षा विभाग के बजट में प्रदान की जा रही 50 करोड़ रूपए की राशि का प्रयोग निधि सृजित करने के लिए किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री इस स्कीम के ब्यौरी की घोषणा करेंगे।

44. भारतीय उद्योग और सरकारी निधि प्राप्त अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बीच घनिष्ठ संपर्क विकसित किया जाना होगा। इसलिए मैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त तथा आयकर अधिनियम के अधीन अधिसूचित सरकार द्वारा प्रवर्तित सोसायटियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों की इक्विटी में निवेश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। ये संस्थान अपनी इक्विटी के रूप में मुद्रा ही नहीं बल्कि अपने ज्ञान और जानकारी का निवेश करेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी

45. 21वीं सदी में प्रभुत्व रखने वाला यदि कोई एक विज्ञान है तो वह सूचना प्रौद्योगिकी

है। अगर एक उद्योग, जिसमें भारत विश्व में अग्रणी के रूप में उभर सकता है तो वह सूचना प्रौद्योगिकी है। तथापि, इस क्षमता को पहचानने के लिए हमें सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण और विपणन के लिए एक पूर्णतः नई नीति की आवश्यकता है। इस समय प्रभावी इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क (ई.एच.टी.पी.), सीमित नमनीयता प्रदान करता है। उत्पादन की मात्रा बढ़ाने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने की अनिवार्य आवश्यकता है। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क/निर्यातोन्मुखी यूनिटों/निर्यात संवर्धन क्षेत्र की यूनिटों को 12 महीने की किसी अवधि के दौरान अपने उत्पादों का आधा हिस्सा घरेलू बाजार में बिक्री करने तथा दूसरे आधे हिस्से के निर्यात करने की अनुमति दी जाए। घरेलू बाजार में बिक्री अतिरिक्त सीमाशुल्क सहित पूर्ण सीमाशुल्क के समतुल्य उत्पाद शुल्क के भुगतान पर की जाएगी। नई एकीकृत विनिर्माण स्कीम का ब्योरा नई निर्यात-आयात नीति, जो पहली अप्रैल, 1997 से लागू होगी, में शामिल किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम और प्रत्यक्ष कर अधिनियम

46. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने नया कंपनी विधेयक तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल तथा एक नया प्रत्यक्ष कर विधेयक तैयार करने के लिए एक अन्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इन दोनों दलों ने उत्कृष्ट कार्य किया है और अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इन रिपोर्टों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में अगले सप्ताह रख दी जाएंगी। इनका व्यापक रूप से वितरण भी किया जाएगा। प्रत्येक विधेयक का कार्यचालन प्रारूप तैयार होते ही, उनको भी परिचालित किया जाएगा। मुझे आशा है कि इन दोनों विधेयकों पर विस्तार से, जानकारी से भरपूर विचार-विमर्श किया जाएगा। मैं नए कंपनी विधेयक को सदन में मानसून सत्र के दौरान तथा नए प्रत्यक्ष कर विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

बीमा

47. न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम आधारभूत संरचना को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। भारत आधारभूत संरचना रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है और अब हमें उस रिपोर्ट को कार्यान्वित करना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता निधियों की है और वह भी दीर्घावधिक निधियों की। इसी कारण से न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम में कहा गया था कि "आधारभूत संरचना विकास और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बीच जबरदस्त संबंध है। आधारभूत संरचना के लिए दीर्घावधिक निधियों की आवश्यकता है।" माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि दीर्घावधिक निधियां पेंशन और बीमा क्षेत्रों में हैं।

48. बीमा क्षेत्र में हमारी प्रमुख कंपनियां जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम हैं। एक लम्बे अंतराल के पश्चात् साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम के कर्मि-मंडल में पूरे सदस्य नियुक्त किए गए हैं। हमने जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत उन्हें गैर-अनुसूचित, गैर-संघीय निवेश करने, अपने कर्मचारियों और एजेंटों की सेवा शर्तों का निर्धारण करने, नियम बनाने तथा

कुछ अन्य शक्तियाँ प्रदान करना शामिल है। उचित समय पर, जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

49. मौजूदा कानूनों के अंतर्गत, एक पुरानी परिभाषा के अनुसार पेंशन निधियों को जीवन बीमा के व्यापार में शामिल किया जाता है। तथापि, यह स्वतः स्पष्ट है कि पेंशन और बीमा दोनों अलग-अलग प्रकार के लाभ हैं और अलग-अलग प्रकार के व्यापार हैं। जहाँ, जीवन बीमा व्यापार में जीवन बीमा निगम का एकाधिकार है, वहीं बहुत सी पेंशन निधियों को सही रूप से छूट दी गई है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। मेरे पूर्ववर्ती, प्रतिष्ठित मंत्री जी की पहल पर, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 1995 में यू.टी.आई. सेवानिवृत्ति लाभ योजना की शुरुआत की। इस योजना में लगभग 80,000 अंशदाता शामिल हुए हैं। मेरा प्रस्ताव है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट को उपरोक्त योजना का विस्तार करके उसे एक पूर्णतया पेंशन निधि में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जाए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने इस संबंध में सरकार से अनुरोध किया है; जीवन बीमा निगम को कोई आपत्ति नहीं है; इसलिए यह उचित होगा कि कानूनों में संशोधन किया जाए।

50. जीवन बीमा निगम ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि निगम को पेंशन संबंधी व्यापार में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने की अनुमति प्रदान की जाए। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि जीवन बीमा निगम को इस अधिकार से वंचित रखा जाए। प्रस्तावित संशोधन से जीवन बीमा निगम को ऐसे संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। इन संशोधनों के पश्चात्, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की पेंशन निधि जीवन बीमा निगम की पेंशन स्कीमों से मुकाबला करेगी।

51. इसी प्रकार, हमारे देश में स्वास्थ्य संबंधी बीमा क्षेत्र का प्रसार बहुत ही कम हुआ है। मात्र लगभग 20 लाख भारतीयों के पास किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी कवच है। जन आरोग्य योजना, जिसे मुश्किल से छः महीने पहले ही शुरू किया गया था, के लगभग 4 लाख पालिसीधारक बन चुके हैं। स्पष्ट रूप से, स्वास्थ्य बीमा संबंधी योजनाओं की मांग है। साधारण बीमा निगम ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसकी 'मेडिकलेम' पालिसी सफल नहीं रही है और वह इस प्रकार के व्यापार में संयुक्त उद्यम को प्रोत्साहन देना चाहेगा। साधारण बीमा निगम को भी विश्वास है कि वह स्वास्थ्य बीमा व्यापार में, प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकेगा। इस संबंध में, मैं आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव रखता हूँ ताकि साधारण बीमा निगम संयुक्त उद्यमों की शुरुआत कर सके तथा स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में चुनिंदा भारतीय कंपनियों को भी प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जा सके।

52. अभी मैंने जो कहा है, वह बीमा क्षेत्र के एक हिस्से की मामूली सी शुरुआत है। जीवन बीमा व्यापार में जीवन बीमा निगम का एकाधिकार जारी रहेगा तथा जीवन-भिन्न, स्वास्थ्य-भिन्न बीमा व्यापार में साधारण बीमा निगम का एकाधिकार बना रहेगा। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि और भारतीय नियंत्रण और अधिकांश भारतीय स्वामित्व वाली केवल कुछ भारतीय कंपनियों को ही स्वास्थ्य बीमा व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। बीमा विनियामक प्राधिकरण (आई.आर.ए.) द्वारा बीमा उद्योग में सेवा प्रदान करने वाली सभी कंपनियों

के लिए विस्तृत नियम बनाए एवं लागू किये जाएंगे। उक्त कंपनियों को बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए विवेकपूर्ण, निवेश संबंधी तथा सामाजिक मानदण्डों को पूरा करना पड़ेगा।

तदर्थ राजकोषीय हुंडियों को समाप्त करना

53. माननीय सदस्यों को याद होगा कि अपने पिछले बजट भाषण में मैंने वायदा किया था कि 1997-98 तक तदर्थ राजकोषीय हुंडियों की प्रणाली को समाप्त करने के लिए इस बजट में मैं ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करूँगा। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कुछ विशिष्ट उपाय तैयार किए हैं।

54. बजट घाटे को वित्तपोषित करने के लिए तदर्थ राजकोषीय हुंडियों की प्रणाली को 1 अप्रैल, 1997 से समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार की प्राप्तियों और अदायगियों में अस्थायी असंगतियों का समायोजन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने की योजना शुरू की जा रही है। सरकार के घाटे को वित्तपोषित करने का यह स्थायी स्रोत नहीं होगा। इन अर्थोपाय अग्रिमों के अतिरिक्त, सरकार के उधार संबंधी कार्यक्रम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता उपलब्ध रहेगी। इस योजना के विवरण की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से की जा रही है।

55. आज मैं जो कर रहा हूँ, वह एक साहसिक और आमूल परिवर्तन है जिससे राजकोषीय व्यवस्था मजबूत होगी तथा मौद्रिक नीति के संचालन में भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। तदर्थ राजकोषीय हुंडियों और निरंतर राजकोषीय हुंडियों को समाप्त करके तथा अर्थोपाय अग्रिम योजना शुरू करने से, सरकार द्वारा निधियों की अल्पावधिक आवश्यकता के संकेतक अथवा मौद्रिक विस्तार की सीमा के रूप में मौजूदा परिभाषा की बजट घाटा संबंधी अवधारणा की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए, यह प्रस्ताव है कि 'बजट घाटा' दर्शाने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए तथा इसके स्थान पर सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) घाटे का प्रमुख संकेतक बन जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार के उधार कार्यक्रम को दी जाने वाली सहायता को बजट दस्तावेजों में "मौद्रिक घाटा" के रूप में दर्शाया जाएगा।

सूचीबद्ध बांड

56. कई देशों ने निवेशकों को मुद्रास्फीति से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने तथा सरकार द्वारा अपनाई गई मुद्रास्फीति-निवारक नीतियों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए विभिन्न किस्मों के सूचीबद्ध बांडों का प्रयोग किया है। मुझे विश्वास है कि भारत के लिए यह उपयुक्त समय है कि ऐसे दस्तावेजों की शुरुआत की जाए। इसलिए, मैं एक पूंजीगत सूचीबद्ध बांड की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखता हूँ जिसके अंतर्गत मूल राशि की वापसी-अदायगी को मुद्रास्फीति से सूचीबद्ध किया जाएगा।

नया अंतरण फार्मूला

57. केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण के लिए अपनाए जाने वाले फार्मूले पर दसवें

वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित चर्चा-पत्र, मैं पहले ही सदन में रख चुका हूँ। राज्यों के विचार भी हमें प्राप्त हो चुके हैं। अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति ने भी इस मामले पर विचार किया है। इन विचार-विमर्शों के आधार पर, मेरा प्रस्ताव है कि दसवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्र और राज्यों के बीच बाँटे जाने वाले करो के एकल विभाज्य पूल बनाने से संबंधित की गई सिफारिश स्वीकार कर ली जाए। आरम्भ में, हम दसवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए 29 प्रतिशत का अनुपात अपनाते हैं। इससे राज्यों को मिलने वाले वर्तमान हिस्से में सुधार होगा। फिर भी, जब हम इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करेंगे तो इस विषय पर हम और विचार-विमर्श करने के इच्छुक हैं। हम अपने इस विश्वास की फिर से पुष्टि करते हैं कि भारतीय राजनीति में एक मजबूत केन्द्र और मजबूत राज्यों की, बल्कि मैं कहूँ कि मजबूत स्थानीय निकायों की आवश्यकता है।

संशोधित अनुमान, 1996-97

58. अब मैं 1996-97 के संशोधित अनुमानों की संक्षेप में चर्चा करूँगा।

59. 1996-97 के बजट अनुमानों में कुल व्यय की राशि 204,660 करोड़ रुपए रखी गई थी। अब यह राशि कम होकर 202,298 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह आयोजना-भिन्न व्यय में 2571 करोड़ रुपए की राशि कम करने तथा आयोजना-व्यय में 209 करोड़ रुपए की वृद्धि करने का निवल प्रभाव है।

60. चालू वर्ष में, आयोजना-भिन्न व्यय की राशि 147,404 करोड़ रुपए रखी गई है। बजट अनुमानों की तुलना में यह 2571 करोड़ रुपए की कमी का छोटक है जो मूलतः पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के संभावित प्रभाव के लिए रखे गए 3000 करोड़ रुपए के प्रावधान की बचत के परिणामस्वरूप हुई है। दूसरी तरफ, हमें विनिवेश से मिलने वाले 4500 करोड़ रुपए की प्रत्याशित प्राप्तियाँ नहीं हुई हैं। इन सब बाधाओं के बावजूद, मैंने वर्ष के दौरान रक्षा के लिए 1700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान रखा है। इसलिए, तुलना करने पर, मेरे विचार से हमने अपनी प्राप्तियों और व्यय को बजट के भीतर ही रखा है।

61. मुझे सबसे अधिक संतुष्टि आयोजना पक्ष से है। हमने केन्द्र सरकार के आयोजना व्यय में पर्याप्त राशि बचाई है। इसलिए विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 2500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करना मेरे लिए संभव हो सका। मैंने वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर को भी 663 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप, कुल आयोजना-व्यय में 209 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यदि मैंने पीटर अर्थात् केन्द्र सरकार से कुछ लिया है तो वह पाल अर्थात् राज्यों को ही दिया है।

62. अक्टूबर, 1996 में प्रधानमंत्री ने चालू परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्त-व्यवस्था सहित उत्तर-पूर्व के लिए नए कार्यों के एक पैकेज की घोषणा की थी, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की आवश्यकता होगी। सरकार नवी योजना में इन परियोजनाओं के लिए निधियाँ आवंटित करेगी। नुमालीगढ़ रिफायनरी के कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है। मैंने

1996-97 के संशोधित अनुमान में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है तथा समय पर इसका कार्य पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए अगले दो वर्षों में पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की जाएगी।

63. बजट अनुमानों में कुल सकल कर राजस्व की राशि जो कि 132,145 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, में, 174 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि होने का अनुमान है, हालांकि केन्द्र के निवल कर राजस्व, जिसकी राशि बजट अनुमानों में 97,310 करोड़ रुपए थी, में लगभग 100 करोड़ रुपए की मामूली कमी आएगी।

64. राजस्व और व्यय के संशोधित अनुमानों को हिसाब में लेने पर, राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के बजट अनुमान से कम होकर 2.3 प्रतिशत रह गया है। राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा यह सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत ही रहेगा। मुझे अफसोस है कि मैं अपने सच्चे आलोचकों को निराश कर रहा हूँ।

65. अपने आलोचकों के बिना हम क्या करेंगे? जैसा सन्त तिरुवल्लुवर ने कहा है:

“इदिप्पराई इल्लाथा इमारा मन्नान

केदुप्पार इलानुम केदुम”

(जो राजा अपने आलोचकों की परवाह नहीं करता, वह शत्रुओं के बिना ही नष्ट हो जाता है)।

बजट अनुमान, 1997-98

66. अब मैं, 1997-98 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा।

67. कुल व्यय 232,481 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें से 62,852 करोड़ रुपए केन्द्रीय, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं की बजटीय सहायता के रूप में तथा शेष 169,629 करोड़ रुपए की राशि आयोजना-भिन्न व्यय के लिए प्रदान की गई है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि आयोजना के लिए 1996-97 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7958 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की वृद्धि होगी जो मेरा विश्वास है अब तक की गई सर्वाधिक वृद्धि है।

68. केन्द्रीय आयोजना को दी जाने वाली बजटीय सहायता को ग्रामीण विकास, रोजगार तथा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों और मानव संसाधन विकास क्षेत्रों में संकेन्द्रित किया जा रहा है। वर्ष 1997-98 में, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के लिये परिव्यय राशि बढ़ाकर 9096 करोड़ रुपए की जा रही है, जो वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमानों की राशि से 1271 करोड़ रुपए अधिक है। वर्ष 1997-98 में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार के लगभग 520 मिलियन मानव कार्यदिवस सृजित होने का अनुमान है। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति

योजना के अंतर्गत, वर्ष 1997-98 के दौरान लगभग 90,000 निवास-स्थानों को सुरक्षित पेय जल प्रदान किया जाएगा।

69. सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए परिव्यय की राशि, जो 1996-97 के संशोधित अनुमानों में 11,785 करोड़ रुपए थी, को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 1997-98 के बजट अनुमान में 15,707 करोड़ रुपए किया जा रहा है। महत्वपूर्ण वृद्धियां शहरी विकास (775 करोड़ रुपए), सामान्य शिक्षा (1189 करोड़ रुपए), तकनीकी शिक्षा (132 करोड़ रुपए), परिवार कल्याण (282 करोड़ रुपए) तथा जलापूर्ति और सफाई (312 करोड़ रुपए) के अंतर्गत की गई हैं।

70. विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए 1870 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जबकि वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 1584 करोड़ रुपए थी।

71. मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान के लिए 40 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम को 41 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है।

72. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के लिए 96 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है। विकलांगों के कल्याण के लिए मैं 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूँ तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के लिए मैं 28 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा हूँ।

73. वर्ष 1997-98 में आयोजना-भिन्न व्यय की कुल राशि 169,629 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ब्याज अदायगियों की राशि 68,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

74. देशी उर्वरकों पर उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता राशि को वर्ष 1997-98 में बढ़ाकर 5240 करोड़ रुपए किया जा रहा है जब कि 1996-97 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 4743 करोड़ रुपए थी। इसके अतिरिक्त, आयातित उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1997-98 में बढ़ाकर 1950 करोड़ रुपए किया जा रहा है जब कि 1996-97 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 1350 करोड़ रुपए थी। विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर मिलने वाली आर्थिक सहायता को 1997-98 में बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जा रहा है जबकि 1996-97 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 1674 करोड़ रुपए थी।

75. वर्ष 1997-98 में खाद्यान्नों और चीनी संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 7500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की जा रही है, जो 1996-97 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1434 करोड़ रुपए अधिक है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जब देश भर में दोहरी कार्ड प्रणाली आरम्भ हो जाएगी, तब यदि इसके लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता हुई तो मैं वह राशि प्रदान करूँगा। मैं अपना हृदय खोलकर नहीं दिखा सकता परंतु मेरा मन बहुत कुछ करना चाहता है।

76. रक्षा के लिए रखे गए परिव्यय का मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। रक्षा के लिए 35,620 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है जिसमें पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 3620 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। विगत में, रक्षा सेवाओं के राजस्व व्यय के लिए आमतौर पर कम प्रावधान रखा जाता रहा है। इस वर्ष, मैंने रक्षा मंत्रालय से राजस्व व्यय की पूर्ण व्यवस्था करने के लिए कहा है। पूंजी खाते में अभी मैं 8907 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूँ, जो 1996-97 के संशोधित अनुमान से 402 करोड़ रुपए अधिक है। लेकिन इसके साथ ही मैं यह वायदा करता हूँ और दृढ़ आश्वासन देता हूँ कि वर्ष के दौरान पूंजी व्यय संबंधी रक्षा सेवाओं की किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय इस संबंध में मेरे विचार भी सही हैं।

77. पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कर्मचारियों के लिए 4205 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है; इसमें रक्षा और रेलवे कर्मचारी शामिल नहीं हैं, जिनके लिए इस बजट तथा रेलवे बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। वेतन आयोग की सिफारिशों पर स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार शीघ्रता से कार्रवाई की जा रही है।

78. सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को दी जाने वाली सहायता हेतु आयोजना-भिन्न प्रावधान में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1996-97 में, हमने भारत यंत्र निगम, भारत भारी उद्योग निगम, हिन्दुस्तान कागज निगम, स्कूटर इंडिया, एचईसी, तथा भारत रिफ़ैक्ट्रीज के लिए पुनरुद्धार पैकेज प्रदान किया था। 1997-98 के लिए, मैं आयोजना-भिन्न ऋणों के रूप में 1107 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रख रहा हूँ और मुझे आशा है कि अगले वर्ष के दौरान हम और अधिक पुनःसंरचित प्रस्तावों को अनुमोदित करेंगे।

राजस्व प्राप्तियाँ

79. अब मैं राजस्व प्राप्तियों की चर्चा करूंगा।

80. कराधान की मौजूदा दरों पर, सकल कर राजस्व 153,347 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। राज्यों के करों के हिस्से के रूप में 40,254 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के पश्चात्, केन्द्र का निवल कर राजस्व 113,094 करोड़ रुपए होगा। कर-भिन्न राजस्वों में भी अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 1997-98 में इस शीर्ष के अधीन 39,749 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है। मैंने सेल्यूलर और बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के निजी प्रचालकों से लाइसेंस शुल्क के रूप में 3681 करोड़ रुपए का ऋण लिया है।

81. केन्द्र के लिए कर-भिन्न प्राप्तियों सहित निवल राजस्व प्राप्तियाँ 1996-97 के संशोधित अनुमान के 130,783 करोड़ रुपए से बढ़कर 1997-98 में 152,843 करोड़ रुपए हो जाने की आशा है।

82. पूंजीगत प्राप्तियों के क्षेत्र में, बाजार उधार 34,425 करोड़ रुपए रखे गये हैं। निवल विदेशी सहायता 2435 करोड़ रुपए होगी। मैं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियों के लिए भी 4800 करोड़ रुपए का ऋण ले रहा हूँ। कराधान की मौजूदा दरों पर कुल प्राप्तियाँ 231,876 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

83. मैं अपने भाषण के भाग "ख" में सकल राजकोषीय घाटों की चर्चा करूंगा।

भाग 'ख'

84. मुझे अपने कर प्रस्तावों के भूमिका-स्वरूप यह कहने दीजिए कि मैंने केन्द्रीय सरकार के निबल कर राजस्वों को 15-16 प्रतिशत के अच्छे स्तर तक बढ़ाने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा प्रस्तावित उपायों के माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

85. अब मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर आता हूँ।

86. न्यूनतम साझा कार्यक्रम यह पुष्टि करता है कि "संयुक्त मोर्चा सरकार कर सुधारों को जारी रखेगी तथा सरकार को वैध तरीके से मिलने वाले राजस्वों को बढ़ाने तथा कर अपवंचन को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपाय करेगी।" मुझे विश्वास है कि एक अच्छी कर नीति का उद्देश्य संतुलित दर, व्यापक कर आधार, अपेक्षाकृत सख्त प्रक्रियात्मक नियम तथा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना होना चाहिए। घरेलू और निगमित क्षेत्र हमारे सर्वोत्तम बचतकर्ता हैं, हमें उन्हें इसका पारितोषिक देना चाहिए। तथापि, एक अन्य दृष्टि से केन्द्र सरकार के लिए सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कर अनुपात, जो इस समय केवल लगभग 10.5 प्रतिशत है, में वृद्धि करना आवश्यक है ताकि सरकारी निवेश तथा सामाजिक क्षेत्र के व्यय की आवश्यकताओं की सम्पूर्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार के कुल कर राजस्वों में प्रत्यक्ष करों का अनुपात बढ़ाना चाहिए।

87. यह नहीं कहा जा सकता कि 900 मिलियन से अधिक आबादी वाले देश में केवल 12 मिलियन लोगों पर ही आय-कर लगाया जाता है तथा यह और भी बुरी बात है कि केवल लगभग 12,000 कर-निर्धारिती ही 10 लाख रुपए से अधिक आय कर देने के दायरे में आते हैं। मैं आयकर अधिनियम की धारा 139 में संशोधन करके कर तंत्र को व्यापक बनाने की शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरा प्रस्ताव यह है कि बड़े महानगरों के निवासियों को जो निम्नलिखित किन्हीं दो आर्थिक मानदण्डों अर्थात् चार पहिए वाले वाहन का स्वामित्व, कतिपय निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाली अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण, टेलीफोन का स्वामित्व और पिछले वर्ष में विदेश यात्रा, को पूरा करते हैं, सामान्यतया कर-योग्य स्तरों के अन्तर्गत आना चाहिए तथा उन्हें स्वैच्छिक रूप से अपनी कर विवरणियां

दाखिल करनी चाहिए। मेरा उनसे निवेदन है कि वे हमारे इस प्रयास में सहयोग दें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है, तो आयकर विभाग उन्हें एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उनसे अपनी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा ताकि उनसे देय कर यदि हों तो उनकी वसूली की जा सके। जो लोग स्पष्टतया बेहतर स्थिति में रहते हैं उन्हें आयकर विभाग के अभिलेखों में अपना नाम पाकर संतुष्ट होना चाहिए।

88. इसी उद्देश्य से मैं फुटकर व्यापारियों के लिए एक नई अनुमानित आय योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी करता हूँ। यह योजना 40 लाख रुपए से कम की कुल बिक्री वाले किसी माल या पण्य-वस्तु के फुटकर व्यापार-व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों पर लागू होगी। वर्तमान छूट सीमा को देखते हुए 8 लाख रुपए से कम की कुल बिक्री वाले व्यापारी को यह छूट प्राप्त होगी। व्यापारी के आय का अनुमान कुल बिक्री के 5 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। जो कर-निर्धारिती इस सीमा से कम आय दर्शाते हुए विवरणी प्रस्तुत करते हैं उन्हें लेखा-पुस्तिकाएं रखनी होंगी तथा अपने लेखों की लेखा-परीक्षा करानी होगी।

89. उपर्युक्त उपायों से धारा 115ट की आम तौर से 1400 रुपए योजना के रूप में प्रसिद्ध मौजूदा प्रकल्पित योजना, जिससे वांछित परिणाम नहीं मिले हैं, समाप्त की जा रही है।

90. सदस्यों को याद होगा कि मैंने अपने पिछले बजट भाषण में पहले आय-स्तर के लिए आय कर की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी थी। मुझे विश्वास है कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम था। यदि हम अन्य विकासशील एशियाई देशों के तुलनात्मक आयकर स्तरों की ओर देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में कर की दरें अभी भी ऊँची हैं और कर-अपवंचन का एक महत्वपूर्ण कारण बनती हैं। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि कराधान की संतुलित दरों से बचतों को प्रोत्साहन मिलता है, संवृद्धि होती है तथा स्वैच्छिक अनुपालन की प्रेरणा मिलती है। मुझे बहुत से माननीय सदस्यों का विवेकपूर्ण परामर्श भी प्राप्त हुआ है। इसलिए मैंने व्यक्तिगत आय कर की दरों में महत्वपूर्ण तरीके से सभी स्तरों पर कमी करने का निश्चय किया है। 15, 30 और 40 प्रतिशत की वर्तमान दरों को 10, 20 तथा 30 प्रतिशत की नई दरों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह दर 40,000 रुपए से 60,000

रुपए के पहले स्तर पर 10 प्रतिशत, 60,000 रुपए से 150,000 रुपए के स्तर पर 20 प्रतिशत तथा 150,000 से ऊपर के सभी आय स्तरों के लिए 30 प्रतिशत होगी।

91. नई कर दरें इतनी संतुलित हैं कि छूट सीमा बढ़ाने का अब कोई औचित्य नहीं है। तथापि, वेतनभोगी व्यक्तियों को कुछ राहत मिलनी चाहिए। इसलिए मैं मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ जो कि अब से सभी वेतनभोगी कर्दाताओं पर समान रूप से लागू होगी। 75,000 रुपए वार्षिक वेतन लेने वाले तथा भविष्य निधि में उसके 10 प्रतिशत का अंशदान करने वाले कर्मचारी को अब कोई कर नहीं देना होगा।

92. राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि सरकार को 'काला धन' को उत्पादक प्रयोजनों के काम में लाने की योजना पर विचार करना चाहिए। मैंने आर्थिक और नैतिक दलीलों की तुलना की है। मैंने विभिन्न विकल्पों पर विचार किया है और मेरा विश्वास है कि यह समय एक स्वेच्छिक अनुपालन योजना शुरू करने के लिए उपयुक्त है। यह एक साधारण योजना होगी जिसके अन्तर्गत निधियों के स्रोत के वर्ष अथवा स्वरूप पर ध्यान दिए बिना या तो नकद, प्रतिभूतियों या परिसम्पत्तियों चाहे भारत में धारित हों या विदेश में, के रूप में प्रकट की गई धनराशि कर के संशोधित उच्चतम दर से प्रभार्य होगी। ब्याज और जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा। आयकर, धन कर तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाई से छूट दी जाएगी। इस योजना के प्रारम्भ होने की तारीख अलग से अधिसूचित की जाएगी, लेकिन यह योजना 31 दिसम्बर, 1997 को समाप्त हो जाएगी। कुल संसाधनों में से, जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया जा सकता है, काफी हिस्सा-77.5 प्रतिशत-राज्य सरकारों को मिलेगा। मुझे आशा है कि वे लोगों को इस नए अवसर का लाभ उठाने के लिए आकर्षित करने हेतु हमारे प्रयास में सहयोग देंगे जो कि उन लोगों के लिए है जो विगत में वैध करों का भुगतान नहीं कर पाए हैं। केन्द्र सरकार को जो हिस्सा उपलब्ध होगा वह पूर्णतः बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम तथा आधारभूत संरचना वाली आवश्यकताओं के वित्तपोषण में लगेगा।

93. मैं हमारे वरिष्ठ नागरिकों को कुछ और राहत देने का भी प्रस्ताव करता हूँ। मैं उन्हें उपलब्ध छूट की दर को 10,000 रुपए की सीमा तक मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रकार 1 लाख रुपए तक की आय वाले किसी वरिष्ठ नागरिक को कोई कर नहीं देना होगा। इससे अधिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी इस छूट सीमा का लाभ मिलेगा लेकिन उन पर 1 लाख रुपए के अधिकतम निर्धारित स्तर से ऊपर कर लगेगा।

94. मुख्य मंत्रियों की माँगों के जवाब में, मैं मुख्य मंत्री राहत कोष या उप-राज्यपाल की राहत निधि में किए गए दानों के संबंध में 100 प्रतिशत की कटौती की व्यवस्था करने के लिए आय कर अधिनियम की धारा 80छ में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

95. कंपनी कर की चर्चा करते हुए मैंने अपने पिछले बजट में अधिभार की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दी थी और यह आशा व्यक्त की थी कि मैं अपने अगले बजट में भी ऐसा ही कदम उठाऊंगा। मैं कंपनियों पर शेष अधिभार समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

96. कंपनियों को नए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं देशी और विदेशी दोनों कंपनियों पर लागू कर दर कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। देशी कंपनियों के लिए दर अब 35 प्रतिशत और विदेशी कंपनियों के लिए 48 प्रतिशत होगी। बेहतर अनुपालन के अतिरिक्त कंपनी दरों में कमी से विकास प्रक्रिया में अधिक गति मिलना, संपूर्ण रूप से तीव्रकारी लाभदायक प्रभाव सृजित करना और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित होना चाहिए।

97. कंपनी क्षेत्र से यह भी मांग की गई है कि विदेशी कंपनियों की देय रायल्टी और तकनीकी सेवा फीस पर 30 प्रतिशत की दर बहुत अधिक है और प्रौद्योगिकी अंतरण में बाधा बनती है। इसलिए मैं इस दर को घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

98. मुझे अनिवासी भारतीयों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि उनके मामले में प्रतिभूतियों के अंतरण से होने वाली पूंजी अभिलाभ कर दर विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में लागू दर के समान होनी चाहिए। मैं उनकी मांग को उचित समझता हूँ और तदनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि इस दर को मौजूदा 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए।

99. कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट), जिसे पिछले वर्ष शुरू किया गया था, व्यापक बहस का विषय रहा है। उपबंधों के निरसन अथवा समीक्षा करने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मुझे डर है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए आर्थिक मूलाधार पूर्णतः परिवर्तित नहीं किए गए हैं और मैं इस अनुरोध को कि पिछले वर्ष लागू उपबंध पूर्णतः वापस ले लिए जाएं, स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। तथापि, वह तरीका, जिसमें कर प्रभाय और संग्रहित होगा, समीक्षा का मामला बनता है। इसलिए मैं, न्यूनतम वैकल्पिक कर के उपबंधों में निम्नलिखित परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ:-

- (i) निर्यात लाभों की न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट होगी और यह धारा 80जजग के अंतर्गत पूर्ण कटौती के पात्र होंगे।
- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के संबंध में एक ऋण प्रणाली शुरू की जाएगी। जब कोई कंपनी न्यूनतम वैकल्पिक कर अदा करती है तो उसके द्वारा अर्जित कर ऋण उसे 5 निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आगे ले जाने की अनुमति होगी और उस निर्धारण वर्ष में जब नियमित कर देय हो जाता है, नियमित कर और न्यूनतम वैकल्पिक कर के अधीन परिकलित कर के बीच अंतर को उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण के एवज में समंजित किया जाएगा। इस प्रकार, कंपनी कर की प्रस्तावित नई दर पर शून्य कर कंपनियों सहित प्रत्येक कंपनी को अपने खाता लाभों पर कम से कम 10.5 प्रतिशत का आयकर अदा करना होगा।

100. कई वर्षों से जोरदार बहस का दूसरा क्षेत्र लाभों पर कर के विषय से संबंधित है। मैं इस बहस को समाप्त करना चाहता हूँ। इसलिए मैं शेयरधारक को प्राप्त होने वाले लाभों पर कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

101. कुछ कंपनियाँ अत्यधिक लाभों का वितरित करती हैं। आदर्शतः उन्हें अपने अधिकांश लाभों को अपने पास रखना और उन्हें नए निवेशों में लगाना चाहिए। मैं उन कंपनियों, जो भावी विकास में निवेश करती हैं, को पुरस्कृत करना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस प्रकार वितरित राशि पर 10 प्रतिशत की मामूली दर पर वितरित लाभों पर कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। यह कर कंपनी पर लगेगा तथा इससे शेयरधारक प्रभावित नहीं होगा।

102. उत्कृष्ट प्रतिभूतियों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मैं ऐसी प्रतिभूतियों पर स्रोत पर कर की कटौती समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों अथवा अनुमोदित म्यूचुअल फंड से प्राप्त आय के संबंध में उपलब्ध कटौती सीमा के समान ही आयकर अधिनियम की धारा 80ठ के अधीन 15,000 रुपये की उच्चतर कटौती सीमा में उत्कृष्ट प्रतिभूतियों को शामिल करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

103. मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूँ कि दूरसंचार आधारभूत संरचना का दर्जा प्राप्त करेगा। इसलिए मैं इस क्षेत्र को निम्नलिखित लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ :-

- (i) धारा 80झक के अधीन करावकाश;
- (ii) लाइसेंस शुल्कों का शोधन, और
- (iii) धारा 88 के अधीन कर संबंधी छूट के प्रयोजन के लिए दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली सरकारी कंपनी के डिबेंचरों और इक्विटी शेयरों में किए गए निवेश को शामिल करना।

104. पर्यटन संबंधी आधारभूत संरचना के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं उन नए होटलों, जो पहाड़ी क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र अथवा तीर्थस्थान या पर्यटन के महत्व वाले निर्दिष्ट स्थान में अवस्थित हैं, के संबंध में लाभों के 50 प्रतिशत की कटौती देने का प्रस्ताव करता हूँ। इन होटलों को व्यय कर से भी छूट प्रदान की जाएगी। चार महानगरों को छोड़कर अन्य स्थानों में अवस्थित होटलों के संबंध में यह कटौती लाभों का केवल 30 प्रतिशत होगी।

105. वित्तीय मध्यस्थता पर कर लगाना मजबूत लोक वित्त के सिद्धान्तों के विपरीत है। बैंकों सहित ऋण संस्थाओं को ऋणों तथा अग्रिमों से होने वाली ब्याज संबंधी आय पर आज 3 प्रतिशत की दर से ब्याज कर लगाया जाता है। मैं इसे घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ और मुझे आशा है कि इस कर को पूर्णतः समाप्त किया जा सकेगा। यह उधार लेने की लागत कम करने में सहायक होगा।

106. सरलीकरण के उपाय के रूप में, उचित व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए खर्च किए गए विज्ञापन, यात्रा, होटल व्यय, मनोरंजन व्यय आदि के लिए कृत्रिम अस्वीकृतियों को हटाने की व्यवस्था करने हेतु मैं आयकर अधिनियम की धारा 37 को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

107. मैंने उन बहुत सी छूटों, जो संविधि-संग्रह पर बनी हुई हैं और अपनी प्रासंगिकता अथवा मूलाधार खो चुकी हैं, को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इनमें धारा 10(15क), 10(26कक), 80छछ और 80जज के अधीन दी जाने वाली छूट और कटौतियां शामिल हैं।

108. अब मैं अपने अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों पर आता हूँ।

109. अप्रत्यक्ष करों के संबंध में न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम में यह निर्दिष्ट किया गया है: "भारत के टैरिफ को विश्व स्तरों के अनुरूप लाने के लक्ष्य की दिशा में की गई प्रगति का मापन और महत्व-निर्धारण किया जाएगा।"

110. एकाधिक अवसरों पर मैंने यह स्पष्ट किया है कि हम इस शताब्दी के अन्त तक एशियान (एएसईएन) देशों में प्रचलित औसत टैरिफ स्तर प्राप्त कर लेंगे। इससे भारतीय उद्योग को इन परिवर्तनों के साथ समंजन करने का समय मिलेगा। इस वर्ष के प्रस्तावों को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

111. मैं सीमाशुल्क की अधिकतम दर को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

112. पूंजीगत वस्तुओं पर सीमाशुल्क के उच्च स्तर सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को आकृष्ट करने की हमारी नीति के अनुरूप नहीं हैं। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में ग्रीनफील्ड निवेशों को विश्वव्यापी स्तर पर प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। मैंने भारतीय उद्योग की आवश्यकताओं को पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की अपेक्षाओं के अनुरूप समंजित करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क में 25 प्रतिशत से मामूली कमी करके 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। 20 प्रतिशत की यह घटी हुई दर परियोजना आयातों पर भी लागू होगी। अगले दो से तीन वर्षों के दौरान इन दरों को अन्य विकासशील एशियाई देशों में प्रचलित स्तरों के अनुरूप और समंजित करने की आवश्यकता होगी।

113. मैं योजनाओं, अभिकल्पों तथा आरेखों पर भी सीमाशुल्क लगाने से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

114. इस्पात उद्योग की कई निविष्टियों पर सीमाशुल्क कम किया जा रहा है। मैं कोकिंग कोयले (जिसमें राख का अंश 12 प्रतिशत से कम हो) पर शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत और अपेक्षाकृत अधिक राख अंश वाले कोकिंग कोयले तथा कोक पर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं निकल पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत, फेरो अलाय पर 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत तथा पुनःवेल्लीय इस्पात स्क्रैप पर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इन सभी उपायों से इस्पात उद्योग को अपनी उत्पादन लागत कम करने का लाभ मिलना चाहिए।

115. इस समय लोहा और इस्पात उत्पादों पर सामान्यतया 30 प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क लगता है। मैं इस साल कर संरचना में कोई मुख्य परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं करता हूँ। तथापि, मैं लोहा और इस्पात के कोल्ड रोल्ड क्वायल पर सीमाशुल्क 30 प्रतिशत से

126. डॉक्टरी देख-भाल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, मैं चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत, कैसर उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाले 15 एमईवी या इससे अधिक के लाइनियर एक्सीलेटरों पर 10 प्रतिशत से 0 प्रतिशत, तथा चश्मे के लेन्स बनाने के लिए अप्थालामिक ब्लैकों पर 50 प्रतिशत से 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

127. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं होटलों के लिए आवश्यक विशिष्ट उपकरणों पर आयात शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत तथा विदेशी पर्यटकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विशिष्ट विशेष खाद्य मदों पर 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

128. मैं सिने फिल्मों तथा अन्य फोटोग्राफिक फिल्मों पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत और कैमरा के पुर्जों पर 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करके फिल्म और फोटोग्राफी उद्योग को भी कुछ राहत देने का प्रस्ताव करता हूँ।

129. मैं असबाब पर सीमाशुल्क 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

130. अब मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपने प्रस्तावों पर आता हूँ।

131. हमारी उत्पाद शुल्क संरचना काफी अधिक जटिल है। कुछ समय पहले तक, हमारे पास करों की दरों में विविधता, अंत-उपयोग की असंख्य छूटें तथा अन्य विरूपण थे। पर्याप्त सरलीकरण किया जा चुका है। विगत जुलाई में, मैंने यह वायदा किया था कि तीन वर्षों के अन्दर हमारे पास चार दरों वाली कर संरचना होगी। मुझे यह मालूम है कि प्रथमतः उत्पाद शुल्क की दरों के फैलाव को कम करना आवश्यक है। मेरा विश्वास है कि हम अन्ततः लगभग 18 प्रतिशत के मध्यम दर की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, मैंने तीन नई दरें अर्थात् 8 प्रतिशत, 13 प्रतिशत और 18 प्रतिशत शुरू की हैं। इस प्रक्रिया में मैंने 20 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की दरों (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों के मामले के सिवाय) को समाप्त कर दिया है। राजस्व के हित में मैंने फिलहाल 15 प्रतिशत की दर बनाए रखी है जो कि धातुओं और कुछ अन्य वस्तुओं पर लागू होगी।

132. तथापि, उत्पाद शुल्क संरचना को अभी भी बहुत सी छूटें मिली हुई हैं। कुछ अपरिहार्य अपवादों के साथ सभी वस्तुओं पर न्यूनतम दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाना चाहिए। मैं अगले वर्ष के बजट में यह कार्य शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

133. सूती धागे पर 5 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क जारी रहेगा।

134. मैं मुरब्बा, जेली, चटनी और शोरबा जैसी वस्तुओं के कुछ मामलों में छूट वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ जिन पर मैं 8 प्रतिशत का नाममात्र का शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी तरह मैं 100 रुपए से अधिक मूल्य वाले पेनों और बाल पाइन्ट पेनों और

पावर-रहित घूप के चक्कों पर 8 प्रतिशत का शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, लेखन स्याही उत्पाद शुल्क से मुक्त रहेगी।

135. बिस्कुट, चीनी की मिठाइयाँ, घुलाई के साबुन, दूध पेस्ट, दूध पाउडर, कांच के रसोई के बरतन-भाड़े और दीवार घड़ियाँ तथा प्रति नग 600 रुपए तक की मूल्य वाली घड़ियों जैसी व्यापक उपभोग वाली बहुत सी वस्तुओं पर मैं उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। 13 प्रतिशत की दर प्रति नग 600 रुपए से अधिक की घड़ियों और दीवार घड़ियों और मशीनरी और पुर्जों, दोपहिया मोटर वाहनों के टायर एवं द्यूब प्रदीप्त द्यूबों और कम्प्यूटर एवं उनके पुर्जों जैसी मर्दों के लिए शुल्क दर होगी। 13 प्रतिशत की घटी हुई यह दर एक्सरे फिल्मों, सफाई के तौलियों, बच्चों के नैपकिन और इसी तरह की सफाई की वस्तुओं पर लागू होगी।

136. बहुत से उत्पादों के संबंध में, मैं उत्पाद शुल्क में 2 प्रतिशत से लेकर 7 प्रतिशत तक की कटौती करने तथा इन पर मध्यम दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। तदनुसार, 18 प्रतिशत की मध्यम दर कोको और कोको से तैयार किए गए पदार्थों, तुरंती काफी, शरबत, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, पेन्ट और रंग-रोगन, इलेक्ट्रिक तार और केबल, प्रसाधन के साबुन, डिटर्जेंट, चमड़े की वस्तुएं, सिन्थेटिक रबड़, फाइबर तथा मिश्रित सिन्थेटिक धागे, कागज तथा गता, प्लास्टिड, यात्रा के सामान तथा बहुत-सी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं सहित कई पण्य वस्तुओं पर लागू होगी।

137. कृषि तथा बागवानी की मशीनरी को उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह छूट मिली हुई है। मैं उत्पाद शुल्क से यह छूट दूध निकालने वाली मशीनों, डेयरी मशीनरी तथा उनके पुर्जों को प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

138. रुग्ण पटसन उद्योग का पुनरुद्धार करने और उनको बढ़ावा देने के लिए मैं सभी पटसन एवं पटसन के उत्पादों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

139. इस समय मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों द्वारा उपकरण एवं उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को सीमाशुल्क से छूट मिली हुई है। देशी उत्पादकों के हित में, मैं ऐसे संस्थानों द्वारा देशी उपकरण एवं उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद को उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

140. मैं पूर्णरूपेण एक अधिक संतुलित उत्पाद शुल्क ढांचा बनाने के लिए कुछ वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क घटाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। ये प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए टेक्सियों और कर्तों पर शुल्क को 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत
- पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न पर शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत

- सौन्दर्य-प्रसाधन एवं शौचालय की वस्तुओं पर शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत
- चमकदार टाइलों पर शुल्क को 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत
- वातानुकूलकों पर शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत।

141. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान वर्जित है। कैंसर और सांस की बीमारियों के विरुद्ध संघर्ष जारी है। मेरा योगदान गैर-फिल्टर सिगरेटों, जिनकी लम्बाई 60 एम.एम. से अधिक न हो, जिन्हें सामान्यतया छोटे सिगरेट कहा जाता है, पर उत्पाद शुल्क 75 रुपए प्रति हजार से बढ़ाकर 90 रुपए प्रति हजार करना होगा। मैंने अन्य श्रेणियों के सिगरेटों पर भी उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी की है। ये बढ़ोत्तरीयाँ 20 रुपए से लेकर 70 रुपए प्रति हजार तक की गई हैं। बीड़ी पर 1993 से उत्पाद शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए मैं बीड़ी पर उत्पाद शुल्क को प्रति हजार 5 रुपए से बढ़ाकर प्रति हजार 6 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। फुटकर मूल्य पर शुल्क के इस परिवर्तन का प्रभाव 20 बीड़ियों के एक बण्डल के लिए मात्र 2 पैसे होगा। जहाँ तक सिगरेटों का संबंध है, प्रत्येक छोटे सिगरेट के लिए यह वृद्धि 15 गुना अधिक होगी।

142. लघु क्षेत्र का हमारे समग्र उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है जिससे लाभकारी रोजगार मिलता है तथा साथ ही हमारे निर्यात उपलब्धियों में भी इसका योगदान है। यह इस सरकार की घोषित नीति है कि लघु उद्योग को दुर्बहनीय प्रक्रियाओं की कठिनाइयों से मुक्त रखा जाए। इस उद्देश्य के अनुरूप ही मैंने लघु इकाइयों के लिए उत्पाद-शुल्क की रियायतों की योजना को मूलतः सरल बना दिया है। मैं एक वित्तीय वर्ष में 30 लाख रुपए तक की निकासियों पर शुल्क की पूरी छूट जारी रखना चाहता हूँ। इसके बाद किसी लघु इकाई को 30 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख रुपए तक की निकासियों पर एक समान दर से उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा बशर्ते कि वह लघु इकाई भुगतान किए गए शुल्क वाली निविष्टियों पर किसी मॉडवेट ऋण का लाभ न उठाती हो। शुल्क की एक समान दर 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए की निकासियों पर मूल्यानुसार 3 प्रतिशत तथा 50 लाख रुपए से लेकर 100 लाख रुपए के बीच की निकासियों पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत होगी। एक समान दर उन सभी विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू होगी जिन पर लघु छूट योजना लागू है। छूट की संशोधित योजना में, लघु इकाइयों के लिए मॉडवेट का लाभ उठाने हेतु पेचीदे रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके लिए वस्तुओं का वर्गीकरण निर्धारित करना भी आवश्यक नहीं होगा।

143. शुल्क भुगतान से बचने पर नियंत्रण लगाने के लिए, मैंने सूती धागे और मानवनिर्मित कृत्रिम धागे जैसी कुछ वस्तुओं को लघु उद्योग छूट योजना के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का निश्चय किया है।

144. अध्यक्ष महोदय, हालाँकि हमारी यह नीति है कि कर दरों को संतुलित किया जाए तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए, फिर भी सरकार कर-अपवचन को रोकने के लिए उतनी

ही प्रतिबद्ध है। यह सूचना मिली है कि प्रेरण भट्ठी, स्टील रि-रोलिंग मिलों आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में उत्पाद-शुल्क का अपवर्चन अधिक होता है और उत्पादन के बारे में ठीक ठीक सूचना नहीं दी जा रही है। मैं उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्पाद शुल्क की वसूली शुरू करके इस समस्या का समाधान करने का प्रस्ताव करता हूँ। उपरोक्त परिवर्तन का कार्यान्वयन करने के लिए उत्पाद शुल्क कानून में उपयुक्त विधायी परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावों का ब्योरा इस सदन में यथा-समय प्रस्तुत किया जाएगा।

145. सामान्य नागरिक बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करता है। मेरे प्रस्तावों- कुछ बढ़ोत्तारियों तथा बहुत सारी कटौतियों के परिणामस्वरूप मुझे विश्वास है कि इन वस्तुओं के कर भार में पर्याप्त कमी आएगी।

146. सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40 प्रतिशत योगदान है। "सेवाएं" "विनिर्मित वस्तुओं" की तरह ही उत्पादक वस्तुएं हैं। इन दोनों पर कर लगाया जाना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत सी सर्वविदित सेवाओं को इसके अन्तर्गत लाने के लिए सेवा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ जैसे-

- माल को सड़क मार्ग से लाना-ले जाना,
- परामर्शी इंजीनियर;
- सीमाशुल्क गृह, स्टीमर तथा निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता,
- हवाई यात्रा अभिकर्ता, टूर ऑपरेटर तथा कार किराया एजेंसियाँ;
- बाह्य खान-पान प्रबंधक, पंडाल ठेकेदार तथा मण्डप रक्षक;
- जन-शक्ति भर्ती अभिकर्ता।

147. सेवा कर संबंधी प्रस्तावों से एक समूचे वर्ष में 1200 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। तथापि, वित्तीय वर्ष 1997-98 के शेष भाग के लिए, मैं 900 करोड़ रुपए का ऋण ले रहा हूँ। मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार करने के लिए, मैं सड़क मार्ग से माल की ढुलाई पर लगाए गए सेवा कर से प्राप्त हुई पर्याप्त आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संसाधनों को बढ़ाया जा सके।

148. पारम्परिक आधार पर, सीमाशुल्क में कटौती से संबंधित मेरे प्रस्तावों से एक वित्तीय वर्ष में 2625 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है तथा उत्पाद शुल्कों के मामले में, मेरे प्रस्ताव मोटे तौर पर राजस्व निष्प्रभावी है। तथापि, अर्थव्यवस्था को जो उत्फुल्लता और संवृद्धि की गति मिलेगी उससे पारम्परिक हिसाबों से परिकलित हमारी हानियों की कहीं अधिक क्षतिपूर्ति हो जाएगी।

149. अब मुझे अपने सहयोगी संचार मंत्री, जिन्होंने आज इसके पहले एक विवरण दिया है, की ओर से कुछ कहना है। कुछ डाक सेवाओं के टैरिफों में संशोधन करना अपरिहार्य हो

गया है। तथापि, ऐसा करने में हमने आम आदमी के हित और व्यापक सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में डाक सेवाओं की भूमिका को ध्यान में रखा है। हालाँकि पंजीकृत समाचार पत्रों के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, साधारण पोस्टकार्ड का मूल्य बढ़ाकर 25 पैसे तथा मुद्रित पोस्टकार्ड का मूल्य 1.50 रुपए किया जा रहा है। अन्तर्देशीय पत्र का मूल्य भी 75 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए तथा लिफाफे का मूल्य 1 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए किया जा रहा है। कुछ अन्य परिवर्तन भी किए जा रहे हैं जिन्हें बजट दस्तावेजों के साथ परिचालित ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है। ये परिवर्तन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे बाद में अधिसूचित किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों से समूचे वर्ष में 367 करोड़ रुपए और 1997-98 के दौरान 305 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। यह मामूली वृद्धि डाक सेवाओं के विकास तथा डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बहुसंख्यक सेवाओं पर घाटे की आंशिक पूर्ति करने के लिए आवश्यक है।

150. सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में उपर्युक्त परिवर्तनों को लागू करने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियाँ यथा-समय सदन के पटल पर रख दी जाएँगी।

151. अध्यक्ष महोदय इतने परिश्रम के पश्चात्, अब मुझे अन्तिम निष्कर्ष पर आना चाहिए। 1997-98 में राजस्व घाटा 30,266 करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% रहा गया है। राजकोषीय घाटा 65,454 करोड़ रुपए बैठता है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है। मैं राजकोषीय सुधार की दिशा जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता से विचलित नहीं हुआ हूँ। इस सदन के समर्थन से तथा जैसा कि न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम में वायदा किया गया है, मैं अगले बजट में राजकोषीय घाटे को 4% से नीचे लाने की आशा करता हूँ।

152. हमारा उद्देश्य तीव्र और व्यापक आधार वाली संवृद्धि को प्राप्त करना होना चाहिए और केवल वही अपेक्षाकृत अधिक रोजगार, बेहतर जीवन-स्तर तथा एक मानवोचित एवं न्यायसंगत समाज का विकास सुनिश्चित कर सकती है। आज जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं वे भारत के लिए अनूठी नहीं हैं। एशिया के हमारे मित्र देशों सहित अन्य देशों ने इसी तरह की चुनौतियों का सामना किया है। जापान ने इसका मार्ग प्रशस्त किया है। अन्य एशियाई देश उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। और अन्ततः चीन का उदाहरण है जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इन देशों ने यह दिखा दिया है कि साहस, विवेक और व्यावहारिकता से वे विश्व में अपना उचित स्थान बना सकते हैं।

153. दंग जियाओ पेंग, जिन्हें हमने कुछ दिन पहले श्रद्धांजलि अर्पित की है, ने एक बार कहा था, "पिछले कुछ वर्षों के हमारे अनुभव से आर्थिक विकास के लिए पूर्णतया यह संभव है कि प्रत्येक कुछ वर्षों में वह एक नई अवस्था में पहुँच जाए। विकास ही ठोस सच्चाई है। भारत की अर्थव्यवस्था भी एक नई अवस्था में पहुँच गई है। छः वर्ष पहले की तुलना में, आज हमारा प्यारा भारत कहीं अधिक मजबूत है।

154. मैं इस सदन और भारतीय जनता से गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर के इस आह्वान की ओर ध्यान देने के लिए निवेदन करूँगा:

"देश देश नन्दिता करी मंदिता ताभा भेरी,
आशिलो जाता बीरब्रिन्दा आशना ताभा घेरी।
दीन आगता ओई, भारत ताबू कयी ?
शाय की रहिला लुप्ता अजी शबा जाना पाश्चात्य ?
लाउक विश्वकर्माभार मिली शाबर शथय"

(तुम्हारी पुकार दुनिया के सभी देशों तक फैल चुकी है और लोग तुम्हारे आसन के चहुँ ओर एकत्र होने लगे हैं। वह दिन आ गया; लेकिन भारत कहां है? क्या वह अभी भी छुपा है, काफी पीछे है? उसे अपना बोझ स्वयं उठाने दो और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने दो)

155. अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह बजट इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

जे. एस. माथुर
उपपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****(Budget Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th February, 1997

F. 15(1)—B(D)/97.—The following is published for general information :—

Budget 1997-98

Speech of

SHRI P. CHIDAMBARAM*Minister of Finance***28th February, 1997****PART A**

Sir,

I rise to present the Budget for the year 1997-98.

Introduction

2. The government headed by Prime Minister Shri Deve Gowda completes 9 months today. When I stood before this House on July 22, 1996, this House received my proposals with a mixture of wonder, curiosity and scepticism. I was, after all, the Finance Minister of the first genuine coalition government at the Centre. I was also the first Finance Minister who belonged to an avowed regional party, albeit with a national outlook.

3. Hon'ble Members will indulge me for a few minutes while I reflect on those eventful days in May 1996. One national party acknowledged that it had lost its claim to form the government. Another tried, but failed. It is in that situation, that regional parties, and certain parties with a larger national presence, came together to form the United Front government. These parties—long regarded as children of a lesser God—have demonstrated that, given the opportunity, they can form a government not only at the State level but also at the Centre. Inspired

by the idea of a truly cooperative federal polity, Chief Ministers have assembled, more often than ever before, at the Inter-State Council, the National Development Council and at Special Conferences to formulate national policies. The formation of the government by the United Front and our efforts to take decisions by a national consensus, in the fiftieth year of India's independence, have deepened and broadened Indian democracy.

4. Hon'ble Members will find that there is a strong continuity between my first Budget and the present one. The foundation of the Budget remains the Common Minimum Programme. The experience of the last eight months has demonstrated the enormous strengths of the programme. Drawing on the CMP, my first Budget articulated seven broad objectives. These objectives embraced vital elements such as growth, basic minimum services, employment, macroeconomic stability, investment (particularly in infrastructure), human development and a viable balance of payments. I believe these objectives remain as valid today as they were eight months ago.

July 1996 Budget Promises

5. On the last occasion, I had made over forty specific promises on policies and programmes. I have carefully taken stock of the situation, and Hon'ble members will be pleased to know that I have fulfilled all these promises, save one, to which I shall refer presently. To recall the more important ones, I am happy to state that we have

- Provided an additional sum of Rs. 2466 crore to the States for seven Basic Minimum Services;
- Funded the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)-II with Rs. 2500 crore;
- Expanded the list of industries eligible for automatic approval for foreign equity investment;
- Set up the Disinvestment Commission and the Tariff Commission;
- Introduced the Jeevan Suraksha and the Jan Arogya insurance schemes; and
- Launched the Accelerated Irrigation Benefit Programme.

6. The one commitment that I have been unable to keep is to set up an Expenditure Management and Reforms Commission. I failed because I wanted an A team and I was not content with a B team. Key members of the A team are in this House and in the Rajya Sabha, and they still elude me. I shall keep trying. Meanwhile, I have not let up on my resolve to keep expenditure within the Budget, and I have achieved a fair measure of success.

Current Economic Situation

7. The Economic Survey 1996-97 was laid in Parliament a few days ago. It provides a detailed and balanced account of the state of the economy. There is indeed much to be done, but there is also much to be proud of. The outstanding feature of the economy is that the GDP has been growing during the last three years at an average rate of 7%. I salute the farmers, the workers, the entrepreneurs and the service providers who have made this possible.

8. The positive features of our economic performance in 1996-97 include:

- Continued high economic growth at 6.8%;
- A strong recovery of growth in agriculture and allied sectors to 3.7%, after a disappointing minus 0.1% in 1995-96;
- Rebound in foodgrains production to 191 million tonnes;
- Manufacturing sector growth at 10.6%; and
- A sizable build up in our foreign currency reserves from US\$ 17.0 billion to US\$ 19.5 billion as on February 27, 1997.

9. I shall not be true to myself or to the country if I did not highlight the areas of weakness. Two areas of great concern are the sharp drop in domestic crude oil production and the sluggish performance of the power sector. Other matters of concern include a deceleration in the growth of exports, a rise in the rate

of inflation and a volatile capital market. Government has addressed these concerns through some far-reaching initiatives in the last three months. I have also fresh proposals in this Budget.

10. Macroeconomic management involves, inevitably, striking a balance between various objectives and considerations. As Hon'ble Members are aware, in 1995-96, the growth in money supply was reduced sharply to 13.2%. Although this helped to contain inflation, it also led to high real interest rates, a widespread perception of a liquidity crunch and a slackening of investment proposals. Since June 1996, corrective action has been taken which has eased the availability of money and brought down the interest rates. The long-delayed increase in the prices of petroleum products and supply-side problems, arising mainly out of lower production and lower procurement of wheat in the last season, exerted pressure on the price level. Government has taken a number of steps to maintain price stability. Paddy production and procurement in the *Kharif* season have been satisfactory and we have adequate stocks of rice. The *Rabi* wheat crop is also very promising and steps will be taken to maximise procurement. At the same time, I would like to make it clear that, if necessary, government will not hesitate to import wheat and other essential articles to counter the pressure on prices. Maintaining price stability is high on the agenda of this government.

11. Apart from supply side management, we have to adopt prudent fiscal and monetary policies that will stabilise prices. For the year 1997-98, government and the RBI will act in concert towards a further reduction in the fiscal deficit, containment of the growth of money supply within 16% and adoption of a liberal import policy for essential commodities. Our goal is to break inflationary expectations and reduce the rate of inflation from the present level.

Poverty Alleviation Programmes

12. Our fight against poverty is not a game in populism. It is a battle at the grassroots level. It is a battle in which, I believe, all of us ought to be on the side of the poor. Those who are poor

re those who do not have land or water or education or opportunity. Our programmes, therefore, revolve around the concerns of the poor. For example

- The flagship programme of the Prime Minister is the Basic Minimum Services plan. As against Rs.2466 crore in the current year, I propose to provide Rs.3300 crore for this programme in 1997-98. This will include Rs.330 crore for slum development.
- The provision for the Accelerated Irrigation Benefit Programme is being enhanced from Rs.900 crore to Rs.1300 crore in 1997-98.
- The Ganga Kalyan Yojana is intended to support farmers to take up schemes for groundwater and surface water utilisation through a mixture of subsidy, maintenance support and credit arrangements. Rs.200 crore is being provided in 1997-98.
- On August 15, 1997, the Prime Minister will inaugurate the Kasturba Gandhi Shiksha Yojana, a programme to establish special schools for girl children in the districts which have a particularly low female literacy rate. I have placed Rs.250 crore in the Budget for 1997-98.
- All current self-employment schemes, addressed to different target groups such as PMRY, IRDP, NRY etc., will be re-orientated to provide skill-based training, entrepreneurship development and subsidy-linked bank credit to 1 million youth to empower them to start viable small businesses.

13. Our government believes that poverty alleviation programmes are important instruments in the fight against poverty. While maintaining the large outlays for these programmes, it is necessary to rationalise their number and make them more focussed and effective. The Planning Commission is now engaged in a comprehensive exercise and the revised portfolio of poverty alleviation programmes will be implemented with effect from April 1, 1997.

Rural Credit

14. Agriculture is the lifeblood of our economy. The CMP calls for a doubling of the flow of credit to agriculture and agro-industries within five years. In 1996-97, the first year of this government, it is estimated that credit flow to agriculture will increase from about Rs.22,000 crore to nearly Rs.28,600 crore—an increase of an unprecedented Rs.6,600 crore.

15. Hon'ble Members will be glad to know that the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) has proved to be popular and successful. Under RIDF-I, Rs.2,000 crore was sanctioned for 4,530 projects. By March 1997, disbursements will amount to about Rs.1,400 crore. Under RIDF- II, 8,387 projects worth over Rs.2,500 crore have been sanctioned. RIDF III will be launched in 1997-98 and Rs.2500 crore will be provided. I urge the States to continue to make the best use of these funds.

16. The policy of recapitalising the Regional Rural Banks (RRBs) will continue next year. I am providing Rs.270 crore for this purpose. I also intend to allow a greater role to sponsor banks in the ownership and management of RRBs.

17. NABARD is being strengthened. NABARD has been given Rs.500 crore as advance additional share capital—Rs.100 crore by government and Rs.400 crore by RBI—in the current year. The share capital will be augmented by a similar allocation in 1997-98. I am also glad to announce that, as promised last year, NABARD has promoted and incorporated this month state level agricultural development finance institutions in three States as joint ventures. More will be incorporated next year.

Controls on Agriculture

18. The CMP said that all controls on agricultural products will be reviewed and, wherever found unnecessary, will be abolished. Only some regulations are by the Central government, and a beginning is being made by abolishing a few. The Rice Milling Industries (Regulation) Act, 1958 and the Ginning and Pressing Factories Act, 1925 will be repealed. Licensing, price control and

requisitioning under the Cold Storage Order, 1964 will be removed. The Edible Oils and Edible Oil Seeds Storage Control Order, 1977 and the Cotton Control Order, 1986 will be invoked only in well-defined emergency situations. Domestic futures trading would be resumed in respect of ginned and baled cotton, baled raw jute and jute goods. An International Castor Oil Futures Exchange will be set up. I urge State governments to follow this lead and abolish as many controls as possible.

Small Scale Industry

19. As Hon'ble Members are aware, government has recently enhanced the investment ceiling for plant and machinery of small scale industries (SSIs) to Rs.3 crore and of tiny units to Rs.25 lakhs. In order to ensure that credit is available to all segments of the now-enlarged SSI sector, the RBI is issuing instructions that out of the funds normally available to the SSI sector, 40% will be reserved for units with investment in plant and machinery upto Rs.5 lakhs, 20% for units with investment between Rs.5 lakhs and Rs.25 lakhs and the remaining 40% for other SSI units.

20. Government also announced recently that it will examine carefully the other recommendations of the Abid Hussain Committee on the SSI sector. With a view to reduce wastage in agricultural commodities, improve quality and hygiene and promote exports, the Advisory Committee on reservation and dereservation has recommended that 14 items, now reserved for manufacture in the SSI sector, may be dereserved. 822 items would still remain reserved for production in the SSI sector. Government has accepted these recommendations. The dereserved items include rice milling, dal milling, poultry feed, vinegar, synthetic syrups, biscuits, ice cream, a variety of automobile parts and corrugated paper and boards. It is expected that new investment and improved technology will flow into these businesses.

Housing

21. A constraint on adding to the housing stock of the country is the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976. It

is the intention of the government to move a Bill for amending the Act in this session of Parliament.

22. Indira Awas Yojana was launched to build houses for the poor in rural areas. Housing finance companies provide credit, but the bulk of such credit flows into the urban and semi-urban areas. There are some rural housing credit programmes but they lend meagre amounts upto Rs.10,000. There is virtually no source of credit for the farmer who wishes to build a modest house on his freehold land or to improve or add to his old dwelling. This gap must be filled. In consultation with the National Housing Bank (NHB) and others, I have worked out a plan. Loans, upto Rs.2 lakhs, will be given for building houses on freehold land in rural areas at normal rates of interest, subject to the borrower putting in one-third of the value of the house. NHB has been requested to prepare a scheme in which other organisations will also participate. The Prime Minister will launch the scheme on August 15, 1997 and it is our goal to sanction 50,000 loans in the first year.

Employees' Provident Fund & Gratuity

23. The Central Board of Trustees of the Employees' Provident Fund (EPF) has made specific proposals to make the EPF schemes financially more attractive. Government has also looked at the matter from the point of view of augmenting savings. I am happy to announce the following decisions:

- The rate of contribution in all industries and establishments will be increased from 8.33% to 10% for both employers and employees with effect from March 1, 1997.
- In the scheduled industries where the rate of contribution is now 10%, the Act will be amended to make the rate 12% for both employers and employees.
- The requirement of keeping 20% of incremental PF amounts in the Special Deposit Scheme (SDS) will be withdrawn with effect from April 1, 1997 and the Board

of Trustees will be free to invest this portion of the funds in any of the other three kinds of permitted securities.

24. In 1995, the Central government enhanced the ceiling on the amount of gratuity payable from Rs.1 lakh to Rs.2.5 lakh for Central government employees. I am now pleased to announce that the benefit will be extended to all employees covered under the Payment of Gratuity Act, 1972, which will be amended for this purpose.

Public Sector Autonomy

25. The CMP promised that “the United Front government will identify public sector companies that have comparative advantages and will support them in their drive to become global giants.” To begin with, nine well-performing public sector enterprises, the *Navaratnas*, have been identified. These are IOC, ONGC, HPCL, BPCL, IPCL, VSNL, BHEL, SAIL and NTPC. The Industry Minister will shortly unveil a package of measures that will help them achieve this objective. He will also make a full statement on managerial and commercial autonomy to all PSUs.

26. In the meanwhile, government has decided to delegate more monetary powers to the Boards of profit-making enterprises. For these PSUs, the existing limits for capital expenditure that can be incurred without the prior approval of the government is being doubled straight-away, and where the gross block is over Rs.500 crore, the limit will be Rs.100 crore.

Disinvestment

27. The Disinvestment Commission was constituted in August, 1996 and 40 PSUs were referred to the Commission for advice. The Commission has submitted its first report. It has made specific recommendations in respect of three companies. We intend to proceed with the disinvestment in these companies along the lines suggested by the Commission. While the Commission will make further reports every month, a second batch of PSUs has been referred to the Commission.

As the Commission has observed "The essence of a long-term disinvestment strategy should be not only to enhance budgetary receipts, but also minimise budgetary support towards unprofitable units while ensuring their long-term viability and sustainable levels of employment in them." Government agrees with this view and I would appeal to Hon'ble Members to take a positive view of disinvestment.

Oil and Gas

28. The country's demand for petroleum products is growing at over 8% per annum, which is faster than the growth of domestic supply. We cannot choke this growth. At the same time, we must reduce our dependence on imported petroleum products. There is no real alternative to increasing the supply. Just 6 of the 26 basins that have potential for oil and gas in India have been explored, and that too only partially. The Minister of State for Petroleum and Natural Gas will be making a detailed statement on the new exploration licensing policy (NELP) shortly. The highlights of the policy are the following:

- Companies, including ONGC and OIL, will be paid the international price of oil for new discoveries made under the NELP;
- Royalty payments will be fixed on an ad valorem basis instead of the present system of specific rates;
- Royalty payments for exploration in deep waters will be charged at half the rate for offshore areas for the first seven years after commencement of commercial production;
- Freedom for marketing crude oil and gas in the domestic market;
- Tax holiday for seven years after commencement of commercial production for blocks in the North-East region;
- ONGC and OIL will get the same duty concessions on import of capital goods under the NELP as private production sharing contracts;

- Cess levied under the Oil Industry Development Act, 1974 will be abolished for the new exploration blocks; and
- A separate petroleum tax code will be put in place as in other countries to facilitate new investments.

It is my fervent hope that Indian and foreign companies will respond positively to this package of measures.

29. In order to ensure that adequate domestic refining capacity is created, I propose to allow refineries to import capital goods during the Ninth Plan period at a concessional duty on par with the fertiliser sector. Domestic capital goods suppliers will also get deemed export status.

Infrastructure

30. The Infrastructure Development Finance Company has been incorporated. Section 80IA of the Income Tax Act grants a five year tax holiday for certain infrastructure projects. Last month, I announced that telecommunication will qualify as infrastructure. I now propose to add Oil Exploration and Industrial Parks to this category.

31. I am also glad to announce that the vexed question of assignability of telecom licences has been resolved and that tripartite agreements are proposed to be entered into among the Department of Telecommunications, the licensee and the lenders.

32. As Commerce Minister, I proposed in the Exim Policy that supply of goods to oil, gas and power projects, if the supplies are made under the procedure of international competitive bidding, should be given the benefits of 'deemed exports'. As Finance Minister, I am glad to accept this wholesome proposal. Details are being notified separately.

33. The National Highway Authority of India (NHAI) is now geared to implement the new policy on roads and

highways. I propose to enhance budget support for NHAI to Rs.500 crore which is a significant step up from Rs.200 crore provided in the current year.

Foreign Investment

34. Foreign Institutional Investors (FIIs) continue to repose great confidence in India. Net FII investment in India is now over US\$ 7 billion. During the course of this year I have expanded the opportunities for such investments. I propose to take one more step at the instance of Indian companies. The limit of aggregate investment in a company by FIIs, NRIs and NRI-OCBs is now 24%. I propose to allow companies to raise this limit to 30%, subject to the condition that the Board of Directors of the company approves the limit and the general body of the company passes a special resolution in this behalf.

35. Venture capital funds are important vehicles for stimulating investments in new ventures. Under the present guidelines they can invest upto 5% of their corpus in the equity of any single company. This is unduly restrictive. The limit is being increased to 20%.

Capital Market

36. Over 20 million Indians have invested their savings in the capital market. The establishment of the first Depository was an important step taken to bring the Indian capital market upto world standards and to protect the interests of the investors. SEBI was asked to suggest more measures. The committee appointed by me to draft a new Companies Bill has also made valuable suggestions. After considering these suggestions, I propose to accept five recommendations:

- The principle of buy-back of shares by companies subject to certain conditions will be introduced in the Companies Act;
- The provisions of Sections 370 and 372 of the Companies Act will be merged and an overall ceiling

of 60% will be kept for intercorporate investment and loans;

- The Companies Act will be amended to provide for nomination facilities for holders of securities;
- Companies raising funds from the capital market will be required to give an annual statement disclosing the end-use of such funds; and
- One time permission will be given to stockbrokers to corporatise their businesses without attracting tax on capital gains, which will be exempted.

37. I am of the firm view that markets will prosper when economic growth continues to be strong, the fiscal deficit is reduced, interest rates decline and investors are reassured that their interests are secure.

FERA and Money Laundering

38. As we progress towards a more open economy with greater trade and investment linkages with the rest of the world, the regulations governing foreign exchange transactions also need to be modernised. It is generally acknowledged that the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 needs to be replaced by a new law consistent with full current account convertibility and our objective of progressively liberalising capital account transactions. Hence, I propose to introduce, later this year, a Bill titled The Foreign Exchange Management Act. An RBI-appointed group is expected to complete the drafting of the Bill shortly.

39. While FERA is being replaced, we will not let up in our effort to curb the laundering of ill-gotten money. A Bill dealing with money laundering is under preparation and I propose to introduce it during this session of Parliament.

Capital Account Convertibility

40. A little while ago I made a reference to capital account convertibility. We are proud of our foreign exchange earners. They have been given the facility of the Export Earners Foreign Currency (EEFC) Account. At present, the total amount in these

accounts is a modest Rs.2000 crore. I propose to expand the scope of the account by allowing the following facilities:

- To open offices abroad and to meet the expenses thereof; and
- To make investments from the balance in the account in overseas joint ventures upto the limit of US\$ 15 million, without reference to the RBI.

41. I also believe that the time has come for preparatory work towards capital account convertibility. This is a cherished goal. It is also a matter of great sensitivity. Hence, I shall not make any commitment. For the present, I am asking RBI to appoint a group of experts to lay out the road map towards capital account convertibility, prescribe the economic parameters which have to be achieved at each milestone and work out a detailed time table for achieving the goal. I believe the appointment of such a group will send a powerful signal to the world about our determination to join the ranks of front-line nations.

Science and Technology

42. My last budget was viewed in certain quarters as science and technology-friendly. Flattery has its rewards, and I intend to strengthen my friendship with the scientific community. I propose to take the following initiatives:

- The scheme to match every additional commercial rupee earned by CSIR and ICAR laboratories, as well as the IITs, will continue on a permanent basis.
- The Technology Development Board, established to accelerate the commercialisation of indigenous technology, has identified 16 projects that are commercially viable in the fields of agriculture, health, chemicals and pharmaceuticals. In 1996-97, I provided Rs.30 crore to the Technology Development Fund. I propose to increase the allocation in 1997-98 to Rs.70 crore.

43. Tomorrow's technology is based on today's science. I am concerned that there is declining interest in the learning of sciences in schools and colleges. I hold the view that an MBA — even if he is from Harvard — is not a patch on a scientist. On the occasion of the 50th anniversary of our Independence, we will launch the "Swarnajayanti" fellowships. Outstanding scientists below the age of 45 will be assisted to attain and sustain world class levels in science. A sum of Rs.50 crore in the Department of Education's budget will be used to create a corpus. The Minister of State for Science and Technology will announce the details of the scheme.

44. Closer linkages have to be developed between Indian industry and publicly-funded research laboratories. Hence, I propose to allow government-promoted societies recognised by the Department of Scientific and Industrial Research and notified under the Income Tax Act to invest in the equity of private sector companies. These institutions will invest not money but their knowledge and know-how as their equity.

Information Technology

45. If there is one science that will dominate the 21st century, it is information technology. If there is one industry in which India can emerge as a world leader, it is information technology. However, for this potential to be realised, we need a completely new policy for manufacturing and marketing IT products. The Electronic Hardware Technology Park (EHTP) Scheme, presently in force, gives limited flexibility. There is an imperative need to increase production volumes and attract foreign direct investment. Accordingly, it has been decided that EHTP/EOU/EPZ units in electronic hardware may be permitted to sell one half of the value of their products, during any 12 month period, in the domestic market and export the other half. The sale in the domestic market will be on payment of excise duty equivalent to full customs duty, including the additional duty of customs. Details of the new unified manufacturing scheme will be incorporated in the new EXIM policy that will be effective from April 1, 1997.

Companies Act and Direct Taxes Act

46. Hon'ble Members will recall that I had set up an expert group to draft a new Companies Bill and another expert committee to prepare a new Direct Taxes Bill. Both groups have done splendid work and have submitted their reports. Copies of the reports will be placed in the Parliament Library next week. They will also be distributed widely. A working draft of each Bill will also be circulated as soon as it is ready. It is my hope that there will be wide and informed debate on the two Bills. It is my intention to bring the new Companies Bill before this House in the monsoon session and the new Direct Taxes Bill in the winter session.

Insurance

47. The CMP accords high priority to infrastructure. The India Infrastructure Report has been published and it now remains for us to implement the report. The critical need is funds, and that too long-term funds. That is why the CMP said, "There is a strong link between infrastructure development and financial sector reforms. Infrastructure needs long-term finances." Hon'ble Members are fully aware that long-term funds are in the Pension and the Insurance sectors.

48. Our foremost companies in the insurance sector are LIC and GIC. After a long interval of time, LIC and GIC have been given the full complement of Board members. We have also decided to grant substantial autonomy to LIC and GIC, including the power to make non-scheduled, non-consortium investments, to determine the terms and conditions of service of their employees and agents, to make regulations and some other powers. LIC and GIC will be further strengthened in due course.

49. Under the present laws, pension funds are, by an archaic definition, included in the business of life insurance. However, it is self-evident that pension and insurance are two different benefits and two different businesses. While life insurance is the monopoly of LIC, several pension funds have

been rightly exempted and allowed to operate independently. In 1995, at the instance of my distinguished predecessor, UTI floated the UTI Retirement Benefit Plan. It has attracted about 80,000 subscribers. I propose to allow UTI to expand the above plan into a full-fledged pension fund. UTI has made a request to government in this regard; LIC has no objection; and hence it is appropriate to amend the laws.

50. LIC has also requested government to permit it to promote joint ventures in the pension business. There is no reason to deny LIC this right. The proposed amendment will permit LIC to enter into such joint ventures. After the amendments, UTI's pension fund will compete with LIC's pension schemes.

51. Similarly, the penetration of health insurance cover in our country is distressingly low. Just about 20 lakh Indians have some kind of health cover. The Jan Arogya scheme, launched barely six months ago, has already attracted 4 lakh policy holders. Clearly, there is a demand for health insurance products. GIC has frankly admitted that its Mediclaim policy has not been successful and that it would like to promote joint ventures in this line of business. GIC is also confident of facing competition in the health insurance business. Accordingly, I propose to move necessary amendments to enable GIC to float joint ventures and also to allow entry of selected Indian players in the health insurance sector.

52. What I have outlined is a very modest opening of one segment of the insurance sector. LIC will continue to enjoy a monopoly in the life insurance business and GIC will continue to enjoy a monopoly in the non-life, non-health insurance business. I would also like to make it clear that only a few Indian companies, that is Indian-controlled and with majority Indian ownership, will be permitted to enter the health insurance business. Comprehensive regulations will be made and enforced by the Insurance Regulatory Authority (IRA) for all the service providers in the insurance industry.

They would also have to meet the prudential, investment and social norms laid down by the IRA.

Phasing out of Ad Hoc

53. Hon'ble Members will recall that in my last Budget speech I had promised to present concrete proposals in this Budget to phase out the system of *ad hoc* treasury bills by 1997-98. I am glad to announce that the government and the RBI have worked out the specific measures in this regard.

54. The system of *ad hoc* treasury bills to finance the budget deficit will be discontinued with effect from April 1, 1997. A scheme of ways and means advances (WMA) by the RBI to the Central government is being introduced to accommodate temporary mismatches in the government's receipts and payments. This will not be a permanent source of financing the government's deficit. Besides ways and means advances, RBI's support will be available for the government's borrowing programme. Details of the scheme are being separately announced by the RBI.

55. What I am effecting today is a bold and radical change which will strengthen fiscal discipline and provide greater autonomy to the RBI in the conduct of monetary policy. With the discontinuance of *ad hoc* treasury bills and tap treasury bills, and the introduction of ways and means advances, the concept of Budget deficit, as currently defined, will lose its relevance either as an indicator of short-term requirement of funds by the government or the extent of monetisation. Therefore, it is proposed to discontinue the practice of showing the 'Budget deficit'; instead Gross Fiscal Deficit (GFD) would become the key indicator of deficit. The extent of RBI support to the Central government's borrowing programme will be shown as "Monetised deficit" in the Budget documents.

Indexed Bonds

56. Several countries have used a variety of indexed bonds to provide investors an effective hedge against inflation and to

enhance the credibility of anti-inflationary policies followed by the government. I believe the time is ripe for India to introduce such an instrument. I, therefore, propose to introduce a capital indexed bond where the repayment of the principal amounts will be indexed to inflation.

New Devolution Formula

57. I have already placed in the House a discussion paper on the recommendations of the Tenth Finance Commission (TFC) on the formula to be adopted for devolution of resources from the Centre to the States. The views of the States have been received. The Standing Committee of the Inter-State Council has also considered the matter. Based on these consultations, I propose to accept the recommendation of the TFC to form a single, divisible pool of taxes to be shared between the Centre and the States. To begin with, we shall adopt the proportion of 29% recommended by the TFC. This will be an improvement on the present share of the States. However, we are willing to discuss the matter further when we bring the Constitution Amendment Bill to give effect to the decision. We affirm our belief that the polity of India requires a strong Centre and strong States and, if I may add, strong local bodies.

Revised Estimates for 1996-97

58. I shall now briefly go over the Revised Estimates for 1996-97.

59. The Budget Estimates for 1996-97 had placed the total expenditure at Rs.204,660 crore. This is now expected to come down to Rs.202,298 crore. This is the net effect of a *decrease* of Rs.2571 crore in the non-Plan expenditure and an *increase* of Rs.209 crore in the Plan expenditure.

60. Non-Plan expenditure in the current year is placed at Rs.147,404 crore. This represents a decrease of Rs.2571 crore over the Budget estimates basically on account of saving of Rs.3000 crore in the provision made for the likely impact of the recommendations of the Fifth Pay Commission. On the

other hand, we have not got Rs.4500 crore of anticipated receipts from disinvestment. Despite these constraints, I made an additional provision of Rs.1700 crore for Defence during the year. On balance, therefore, I believe we have managed our receipts and expenditure within the Budget.

61. My greatest satisfaction is on the Plan side. We saved a considerable amount in the Plan expenditure of the Central government. It was, therefore, possible for me to provide an additional Rs.2500 crore to the States as Additional Central Assistance for externally-aided projects. I also provided Rs.663 crore to Jammu and Kashmir during the year. As a result, total Plan expenditure has *increased* by Rs.209 crore. If I have robbed Peter, the Central government, it is only to pay Paul, the States.

62. In October, 1996, the Prime Minister announced a package of initiatives for the North-East, including adequate funding for on-going projects, which will require over Rs.6,000 crore. Government will allocate funds for these projects in the Ninth Plan. The Numaligarh Refinery is making good progress. I have provided Rs.100 crore for the project in the RE for 1996-97 and over the next two years adequate funds will be found to ensure its completion on schedule.

63. The overall gross tax revenue which was estimated at Rs.132,145 crore in the Budget estimates will be marginally higher by Rs.174 crore, although the net tax revenue of the Centre would be marginally less by about Rs.100 crore from the Budget estimate of Rs.97,310 crore.

64. Taking into account the Revised Estimates of revenues and expenditure, the Revenue Deficit has come down from the Budget estimate of 2.5% of GDP to 2.3% of GDP. There is no change in the Budget estimate of the fiscal deficit which would remain at 5% of GDP. I am profoundly sorry to disappoint my well-meaning critics.

65. What will we do without our critics? As Saint Tiruvalluvar said:

*"Idipparai Illatha Emara Mannan
Keduppar Ilanum Kedum"*

(Behold the King who repositeth not on those who can rebuke him/He will perish even when he hath no enemies.)

Budget Estimates for 1997-98

66. I now turn to the Budget Estimates for 1997-98.

67. The total expenditure is estimated at Rs.232,481 crore of which Rs.62,852 crore has been provided as budget support for Central, States and UT Plans and the balance Rs.169,629 crore is for non-Plan expenditure. Hon'ble Members will be pleased to note that the increase in budget support for the Plan will be Rs.7958 crore over RE 1996-97, which is the largest increase ever.

68. Budgetary support to the Central Plan is being concentrated on rural development, employment and poverty alleviation programmes and in the human resource development sectors. For 1997-98, the outlay for the Ministry of Rural Areas and Employment is being increased to Rs.9096 crore, an increase of Rs.1271 crore over the RE for 1996-97. In 1997-98, Jawahar Rozgar Yojana is estimated to generate about 520 million mandays of employment. About 90,000 habitations will be provided safe drinking water during 1997-98 under the Accelerated Rural Water Supply Scheme.

69. The outlay for the Social Services sector is being substantially enhanced from Rs.11,785 crore in RE 1996-97 to Rs.15,707 crore in BE 1997-98. Significant increases are under Urban Development (Rs.775 crore), General Education (Rs.1189 crore), Technical Education (Rs.132 crore), Family Welfare (Rs.282 crore) and Water Supply and Sanitation (Rs.312 crore).

70. The Science and Technology sector is being provided Rs.1870 crore as against Rs.1584 crore in RE 1996-97.

71. The Maulana Azad Education Foundation is being given Rs.40 crore. The National Minorities Development and Finance Corporation is being provided Rs.41 crore.

72. Rs.96 crore is being allocated to the National SC and ST Finance and Development Corporation. For the welfare of the handicapped, I am providing Rs.90 crore and for the National Handicapped Finance and Development Corporation I am giving Rs.28 crore.

73. Total non-Plan expenditure in 1997-98 is estimated to be Rs.169,629 crore. The interest payments are estimated to be Rs.68,000 crore.

74. Fertiliser subsidy on indigenous fertilisers is being enhanced to Rs.5240 crore in 1997-98 from Rs.4743 crore in RE 1996-97. In addition, subsidy on imported fertilisers is being increased to Rs.1950 crore in 1997-98, as against Rs.1350 crore in RE 1996-97. The subsidy on sale of decontrolled fertilisers is being enhanced to Rs.2000 crore in 1997-98 from Rs.1674 crore in RE 1996-97.

75. An amount of Rs.7500 crore is being earmarked for foodgrains and sugar subsidies in 1997-98 representing an increase of Rs.1434 crore over RE 1996-97. When the dual card system under the Targeted PDS takes effect throughout the country, if more funds are required, I shall provide the same. I may not wear my heart on my sleeve, but my heart is in the right place.

76. I would like to make a special mention of the outlay for Defence. Rs.35,620 crore is being provided which includes Rs.3620 crore for implementing the recommendations of the Fifth Pay Commission. In the past, revenue expenditure of the Defence Services had been routinely underprovided. This

year, I have requested the Ministry of Defence to fully provide for the revenue expenditure. On the capital account, for the present, I am providing Rs.8907 crore which is Rs.402 crore more than RE 1996-97, with a clear promise—and I make that solemn undertaking here—that any additional requirement of Defence for capital expenditure will be adequately provided for during the course of the year. Mr Speaker, Sir, my head is also in the right place.

77. A provision of Rs.4205 crore is being made for implementing the recommendations of the Fifth Pay Commission for employees other than Defence and Railway personnel for whom separate provisions have been made in this Budget and in the Railway Budget. The recommendations of the Pay Commission are being processed expeditiously according to established procedure.

78. The non-Plan provision for assistance to the public sector units has been on the increase. In 1996-97, we approved revival packages for Bharat Yantra Nigam, Bharat Bhari Udyog Nigam, Hindustan Paper Corporation, Scooters India, HEC ar Bharat Refractories. For 1997-98, I am providing Rs.1107 crore as non-Plan loans, and I expect that we will approve more restructuring proposals during the course of next year.

Revenue Receipts

79. I now turn to the revenue receipts.

80. Gross tax revenues at the existing rates of taxation are estimated at Rs.153,347 crore. After providing Rs.40,254 crore as the States' share of taxes, the Centre's net tax revenue will be Rs.113,094 crore. Non-tax revenues have also shown healthy buoyancy. The receipts under the head are expected to be Rs.39,749 crore in 1997-98. I have taken credit for Rs.3681 crore as license fee from private operators of cellular and basic telecom services.

81. The net revenue receipts for the Centre, including

non-tax receipts, are expected to increase from Rs.130,783 crore in RE 1996-97 to Rs.152,843 crore in 1997-98.

82. In the area of capital receipts, market borrowings are placed at Rs.34,425 crore. Net external assistance will be Rs.2435 crore. I am also taking credit for receipts from disinvestment of equity in public sector enterprises of Rs.4800 crore. Total receipts at the existing rates of taxation are estimated at Rs.231,876 crore.

83. I shall come to the gross fiscal deficit in Part B of my speech.

PART B

84. Let me preface my tax proposals by saying that I have set for myself the goal of augmenting the net tax revenues of the Central Government by a healthy 15-16%; I believe that through the measures proposed by me we will attain this goal.

85. I shall begin with my direct tax proposals.

86. The CMP affirms that “the United Front government will continue with tax reforms and take other steps to augment revenues legitimately due to the government and to curb tax evasion.” I believe that a good tax policy should aim at moderate rates, a wider tax base, simpler procedural rules and securing greater compliance. Households and the corporate sector are our best savers; we must reward them. From another point of view, however, the tax to GDP ratio for the Central Government, which currently is only around 10.5 per cent, needs to increase to sustain the needs of public investment and social sector expenditure. Moreover, the proportion of direct taxes should increase in the total tax revenues of the government.

87. It is inexplicable that in a country of over 900 million people, only 12 million people are assessed to income-tax and, what is worse, only about 12,000 assesseees are in the tax bracket of income above Rs. 10 lakhs. I intend to make a beginning in widening the tax net by an amendment of Section 139 of the Income-tax Act. My proposal is that residents of large metropolitan cities who satisfy any two of the following economic criteria, namely, ownership of a four-wheel vehicle, occupation of immovable property meeting

certain prescribed criteria, ownership of a telephone and foreign travel in the previous year, should normally fall within the taxable slabs and should voluntarily file their tax returns. I appeal to them to cooperate in our endeavour. If anyone fails to do so, the Income-tax Department would serve upon him a notice obliging him to file his return so that taxes, if due from him, could be collected. Those who live in apparent comfort must have the satisfaction of finding their names in the records of the Income-tax Department.

88. With the same objective, I also propose to introduce a new *Estimated Income Scheme* for retail traders. The scheme will apply to persons engaged in the business of retail trade of any goods or merchandise having a total turnover of less than Rs. 40 lakhs. A trader with a turnover of less than Rs. 8 lakhs will stand exempted, given the present exemption limit. The income of the trader will be estimated at 5 per cent of the total turnover. Assesseees who file a return showing income less than 5% of turnover will be required to maintain books of account and get their accounts audited.

89. With the aforesaid steps, the existing presumptive scheme under section 115K, popularly known as the Rs. 1400 scheme, which has not yielded the desired results, is being discontinued.

90. Members may recall that, last July, I had reduced the income-tax rate for the first income slab from 20 per cent to 15 per cent. It was, I believe, a step in the right direction. If we look at comparative income-tax slabs in other developing Asian countries, it will be evident that tax rates in India are still high and constitute an important reason for tax evasion. It is now widely accepted that moderate rates of taxation encourage

savings, foster growth and motivate voluntary compliance. I have received wise counsel from many Hon'ble Members. I have, therefore, decided to lower the rates of personal income-tax across-the-board in a significant manner. The current rates of 15, 30 and 40 per cent are being replaced by the new rates of 10, 20 and 30 per cent. The rate will be 10 per cent in the first slab of Rs.40,000 to Rs.60,000, 20 per cent in the slab of Rs.60,000 to Rs.150,000 and 30 per cent for all incomes above Rs.150,000.

91. The new tax rates are so moderate that there is now little justification for increasing the exemption limit. However, salaried persons deserve some relief. I, therefore, propose to increase the limit of standard deduction to Rs.20,000, which will, henceforth, apply uniformly to all salaried taxpayers. An employee drawing a salary of Rs.75,000 per annum and contributing 10 per cent thereof to the provident fund would have to pay no tax at all.

92. During the last meeting of the National Development Council, a suggestion was made that the government should think of a scheme to harness 'black money' for productive purposes. I have balanced the economic and the ethical arguments. I have considered various options. And I believe that the time is opportune to introduce a Voluntary Disclosure Scheme. This would be a simple scheme where, irrespective of the year or the nature or the source of the funds, the amount disclosed, either as cash, securities or assets, whether held in India or abroad, would be charged at the revised highest rate of tax. Interest and penalty will be waived. Immunity would be granted from any action under the Income-tax, Wealth tax and the Foreign Exchange Regulation Acts. The date of commencement of the scheme will be notified separately, but the scheme will end on December 31, 1997. Of the total resources which can be secured under the Scheme, a substantial part - 77.5 per cent - will accrue to the State governments. I hope they will cooperate in our endeavour in attracting people to avail of this new opportunity being offered to those who have shied away from paying legitimate taxes in the

past. The share which becomes available to the Central government will go entirely towards financing the Basic Minimum Services programme and infrastructure needs.

93. I also propose to give some further relief to our senior citizens. I propose to increase the rate of rebate available to them to 100 per cent, from the existing 40 per cent, subject to a limit of Rs.10,000. Thus, a senior citizen having an income upto Rs.1 lakh would not have to pay any tax. Senior citizens with higher incomes will also enjoy this exemption limit but will be taxed above the threshold level of Rs.1 lakh.

94. Responding to demands from Chief Ministers, I propose to amend section 80G of the Income-tax Act to provide for 100 per cent deduction in respect of donations made to the Chief Minister's Relief Fund or Lieutenant Governor's Relief Fund.

95. Turning to corporate taxes, I had in my last budget reduced the rate of surcharge from 15 per cent to 7.5 per cent and had expressed the hope that I would take a similar step in my next budget. I propose to abolish the balance surcharge on companies.

96. Corporates should be encouraged to undertake new investments. Hence, I propose to reduce the tax rate applicable to both domestic and foreign companies. The rate for domestic companies will now be 35 per cent and for foreign companies 48 per cent. The reduction in the corporate rates, apart from better compliance, should impart an added momentum to the growth process, create multiplier beneficial effects all around and also attract greater foreign investment.

97. There has also been a demand from the corporate sector that the tax rate of 30 per cent on royalty and technical services fees payable to foreign companies is too high and acts as a hindrance to the transfer of technology. I, therefore, propose to reduce this rate to 20 per cent.

98. I have received requests from non-resident Indians that the capital gains tax rate in their case arising on transfer of securities should be at par with the rate applicable in the case of FIIs. I see merit in their demand and, accordingly, propose that the rate be reduced from the existing 20 per cent to 10 per cent.

99. The Minimum Alternate Tax (MAT) on companies, which was introduced last year, has been the subject of extensive debate. A large number of representations have been received to repeal—or review—the provisions. The economic rationale for MAT has, I am afraid, not been altered and I am unable to accept the request that the provision introduced last year be totally withdrawn. However, there is a case for a review of the manner in which the tax is charged and collected. I, therefore, propose to make the following changes in the provisions of MAT :-

- (i) Export profits will be exempt from MAT and will be eligible for full deduction under section 80HHC.
- (ii) A system of credit will be introduced in respect of the payment of MAT. When a company pays MAT, the tax credit earned by it shall be allowed to be carried forward for a period of 5 assessment years and, in the assessment year when regular tax becomes payable, the difference between the regular tax and tax computed under MAT for that year will be set off against the MAT credit available. Thus, at the proposed new rate of corporate tax, every company including the zero tax companies, would have to pay income-tax of not less than 10.5 per cent on its book profits.

100. Another area of vigorous debate over many years relates to the issue of tax on dividends. I wish to end this debate. Hence, I propose to abolish tax on dividends in the hands of the shareholder.

101. Some companies distribute exorbitant dividends. Ideally, they should retain the bulk of their profits and plough them into fresh investments. I intend to reward companies who invest in future growth. Hence, I propose to levy a tax on distributed profits at the moderate rate of 10 per cent on the amount so distributed. This tax shall be an incidence on the company and shall not be passed on to the shareholder.

102. In order to encourage investments in government securities, called gilts, I propose to abolish Tax Deducted at Source (TDS) on such securities. I also propose to include gilts for the higher deduction limit of Rs.15,000 under section 80L of the Income-tax Act as is available in respect of income received from the units of UTI or approved mutual funds.

103. I have already announced that Telecommunication will qualify as an infrastructure. I, therefore, propose to extend the following benefits to this sector :-

- (i) Tax holiday under section 80 IA;
- (ii) Amortisation of licence fees; and
- (iii) Inclusion of investments made in debentures and equity shares of a public company providing telecommunication services for the purposes of tax rebate under section 88.

104. In order to encourage the development of tourism infrastructure, I propose to give a deduction of 50 per cent of the profits in respect of new hotels which are located in a hilly area or a rural area or a place of pilgrimage or a specified place of tourist importance. These hotels will also be exempted from the levy of expenditure tax. In respect of hotels located in other places, excluding the four metropolitan cities, the deduction shall be only 30 per cent of the profits.

105. Taxing financial intermediation goes contrary to the canons of sound public finance. Today, an interest-tax at the rate of 3 per cent is levied on the interest income of lending

institutions, including banks and NBFCs. I propose to reduce the levy to 2 per cent and I hope to eliminate this levy progressively. This will help to keep down the cost of borrowing.

106. As a measure of simplification, I propose to amend Section 37 of the Income-tax Act to provide for the removal of artificial disallowances on account of advertisement, travelling, hotel expenses, entertainment expenses etc. incurred for legitimate business purposes.

107. I have also decided to eliminate a number of exemptions which continue to remain on the statute book and have since lost their relevance or rationale. These include exemptions and deductions under sections 10 (15A), 10 (26AA), 80GG and 80JJ.

108. Now, I turn to my indirect tax proposals.

109. In relation to indirect taxes the CMP has stipulated: "The progress towards the goal of bringing India's tariffs in accord with world levels will be measured and calibrated."

110. On more than one occasion, I have stated that we would achieve the average level of tariffs prevalent in ASEAN countries by the turn of century. This will give time to Indian industry to adjust to these changes. This year's proposals should be seen in this background.

111. I propose to reduce the peak rate of customs duty from 50% to 40%.

112. High levels of customs duties on capital goods are inconsistent with our policy of attracting the best technology. Greenfield investments in large projects should be globally competitive. I have tried to harmonise the needs of Indian industry with the requirements of the capital goods sector. I, therefore, propose a modest reduction in duty on capital goods from 25% to 20%. This reduced rate of 20% will also apply to project imports. Over the next two to three years these rates would need to be further adjusted to conform to levels prevalent in other developing Asian countries.

113. I also propose to exempt plans, designs and drawings from the levy of customs duty.

114. The customs duty on several inputs for the steel industry is being reduced. I propose to reduce the duty on coking coal (of ash content below 12%) from 5% to 3% and on coking coal of higher ash content, as well as coke, from 20% to 10%. I also propose to reduce the duty on nickel from 20% to 10%, on ferro alloys from 25% to 20% and on re-rollable steel scrap from 30% to 20%. All these measures should benefit the steel industry to reduce its cost of production.

115. Iron and steel products at present generally attract customs duty at 30%. I do not propose to make any major changes in the duty structure this year. However, I propose to reduce the duty on Cold Rolled Coils of iron and steel from 30% to 25% to help the engineering industry. I further propose to reduce the duty on ships brought for breaking from 10% to 5% and on pig iron from 20% to 10%.

116. I propose to reduce the duty on non-coking coal from 20% to 10%. This will help the power sector.

117. Chemicals constitute vital inputs for several downstream industries including the small scale sector. I propose to reduce the duty on organic and inorganic chemicals from 40% to 30%. I also propose to make the following reductions on certain essential chemicals:

- On linear alkylbenzene, from 30% to 20%.
- On methanol, from 30% to 20%.
- On naphthalene, from 30% to 20%
- On phenol, from 30% to 25%.
- On catalysts, from 30% to 25%.

118. I also propose to reduce the customs duty on dyes,

pigments, paints and varnishes, glues, enzymes and modified starches from 40% to 30%. These reductions will significantly benefit our textile industry.

119. Mr. Speaker, Sir, the scheduled dismantling of quantitative restrictions under the Multi Fibre Agreement will expose all textile exporting countries to stiff competition. The Ministry of Textiles have created a "Technology Upgradation Fund" for both the textile and jute industries to enhance the competitive efficiency of these sectors. Our textile industry has, therefore, to upgrade its technologies in the shortest possible time. Last year, I had reduced the customs duty on several kinds of textile machinery to 10%. In order to improve the quality of our garments for exports, this year I propose to add some more processing machines to this category. However, to mitigate any adverse impact on domestic manufacturers, I have decided to allow them to import the components and parts of these machinery at a concessional duty of 10%.

120. As a relief to the woollen textile industry, I propose to reduce the import duty on apparel grade wool from 25% to 20%, on wool waste from 30% to 20% and on woollen and synthetic rags from 30% to 25%. On flax fibre, I propose to reduce the duty from 30% to 20%.

121. In order to conserve our forest resources, I propose to fully exempt wood logs, fuel wood, wood chips, etc. from customs duty.

122. The spread of "Information Technology" has radically altered conventional wisdom on growth strategies. I propose several measures to encourage this industry and to reduce costs. These include:

- Full exemption to computer software.
- Reduction of duty on computer parts, other than populated printed circuit boards, from 20% to 10%.
- Reduction of duty on cartridge tape drive and digital video disc drive from 20% to 10%.

- Reduction of duty on populated printed circuit boards from 30% to 20%.
- Reduction of duty on integrated circuits from 20% to 10%.
- Reduction of duty on colour monitor tubes from 20% to 10%.
- Reduction of duty on colour picture tubes from 35% to 30%.
- Reduction of duty on parts of cellular telephones and pagers from 30% to 20%.
- Reduction of duty on telecom equipment from 40% to 30% and on their parts from 30% to 20%.

123. Ham operators are presently eligible to import specified equipment upto a value of Rs.50,000 at a concessional rate of duty. I propose to raise this limit to Rs.75,000.

124. I propose to reduce the duty on watch parts and movements from 50% to 25% and on watch cases of base metals from 50% to 30%. I also propose to reduce duty on horological materials from 20% to 10%. This will help our watch industry to further enhance their quality.

125. We are all concerned about the menace of growing pollution. In order to help reduce the cost of CNG kits, I have decided to reduce the customs duty on such kits and their parts from 10% to a modest 5%. Similarly, I propose to reduce the customs duty sharply on catalytic converters and their parts to 5% from the existing rate of 25%.

126. To improve the quality of medical care, I propose to reduce the import duty on medical equipment from 30% to 20%; on linear accelerators of 15 MeV and above used for cancer treatment from 10% to 0%; and on ophthalmic blanks for making spectacle lenses from 50% to 20%.

127. To promote tourism, I propose to reduce the import duty on specified equipment required for hotels from 35% to 25% and on specified speciality food items used by foreign tourists from 50% to 25%.

128. I also propose to give some relief to the film and photographic industry by reducing the import duty on cine films and other photographic films from 30% to 25% and on parts of cameras from 50% to 25%.

129. I propose to reduce the customs duty on baggage from 60% to 50%.

130. I now come to my proposals on central excise.

131. Our excise structure is far too complex. Till some time ago, we had a multiplicity of rates, innumerable end-use exemptions and other distortions. Considerable simplification has taken place. Last July, I promised that within three years we shall have a four rate tax structure. I find that, in the first instance, it is necessary to reduce the dispersion in excise rates. I believe that we can eventually gravitate towards a mean rate around 18%. With this objective in view, I have introduced three new rates, namely, 8%, 13% and 18%. In the process I have done away with the rates of 20% and 10% (except in the case of some petroleum products). In the interest of revenue, I have perforce to continue, for the time being, the rate of 15% which will apply to metals and a few other commodities.

132. However, the excise duty structure is still punctuated with many exemptions. All commodities, with some unavoidable exceptions, should be subject to excise duty at a minimum rate. I propose to undertake this exercise in the next year's budget.

133. Cotton yarn will continue to bear an excise duty of 5% only.

134. I propose to withdraw the exemption in a few cases like jams, jellies, sauces and soups where I propose to impose a nominal duty of 8%. Similarly, I propose to levy a duty of 8% on pens and ball point pens exceeding a value of Rs. 100 per piece and on non-power sun glasses. However, writing ink will be free from excise duty.

135. On a number of items of mass consumption like biscuits, sugar confectionery, laundry soap, tooth paste, tooth powder, kitchen and tableware of glass, and clocks and watches of a value upto Rs.600 per piece, I propose to reduce the excise duty from 10% to 8%. A rate of 13% would be applied for watches and clocks above Rs.600 per piece and other items like machinery and parts, tyres and tubes of two-wheeled motor vehicles, fluorescent tubes, and computers and parts thereof. A reduced rate of 13% will also apply to X-ray films, sanitary towels, napkins for babies and similar sanitary articles.

136. In respect of a large number of products, I propose to reduce the excise duty by percentages ranging from 2% to 7% and apply the mean rate. Accordingly, the mean rate of 18% would be applicable to many commodities including cocoa and cocoa preparations, instant coffee, sherbats, organic and inorganic chemicals, paints and dyes, electric wires and cables, toilet soaps, detergents, articles of leather, synthetic rubber, fibres and blended synthetic yarn, paper and paper board, plywood, travel goods and a host of consumer durables.

137. Agricultural and horticultural machinery are fully exempt from excise duty. I propose to extend the exemption from excise duty to milking machines, dairy machinery and their parts.

138. In order to revive and give a thrust to the ailing jute industry, I propose to fully exempt all jute and jute products from excise duty.

139. At present, import of equipment and consumables by recognized research institutions is exempt from customs duty. In the interest of the domestic producer, I propose to allow the purchase of indigenous equipment and consumables by such institutions free of excise duty.

140. I also propose to reduce the duties of excise on certain items in order to bring about a more balanced excise structure on the whole. The changes proposed are:

- Reduction of duty on taxis and cars for the physically handicapped from 30% to 25%.

- Reduction of duty on polyester filament yarn from 40% to 30%.
- Reduction of duty on cosmetics and toilet preparations from 40% to 30%.
- Reduction of duty on glazed tiles from 30% to 25%
- Reduction of duty on airconditioners from 40% to 30%.

141. Mr. Speaker, Sir, smoking in public is banned in Delhi. The fight against cancer and respiratory diseases continues. My contribution will be to increase the excise duty on non-filter cigarettes, not exceeding 60 mm in length, popularly called mini cigarettes, from Rs.75 per thousand to Rs.90 per thousand. I have also increased the excise duty on other categories of cigarettes. The increases range from Rs.20 to Rs.70 per thousand. There has been no increase in the excise duty on biris since 1993. I, therefore, propose to increase the excise duty on biris from Rs.5 per thousand to Rs.6 per thousand. The impact of this duty change on the retail price would only be 2 paise for a bundle of 20 biris. As regards cigarettes, the increase would be 15 times more for every mini cigarette.

142. The small scale sector makes an important contribution to our overall production, provides gainful employment and also contributes to our export effort. It is the declared policy of this Government to free the small scale industry from the rigours of cumbersome procedures. In line with this objective, I have radically simplified the scheme of excise duty concessions for the small scale units. I intend to continue the full exemption from duty on clearances upto Rs.30 lakhs in a financial year. Thereafter, a small scale unit would be required to pay a flat rate of excise duty on clearances beyond Rs.30 lakhs and upto Rs.100 lakhs, if the small scale unit does not avail of any modvat credit on duty paid inputs. The flat rate of duty will be 3% ad-valorem on clearances between Rs.30 to Rs.50 lakhs and 5% ad-valorem on clearances between Rs.50 to Rs.100 lakhs. The flat rate will apply for all specified goods to which the small scale exemption scheme is applicable. In the revised scheme of exemption, the small scale units will not be required to maintain complicated records for

availing modvat. They will also not be required to determine the classification of goods.

143. In order to curb avoidance from payment of duty, I have decided to exclude a few items like cotton yarn and texturised man-made yarn from the purview of the SSI exemption scheme.

144. Mr. Speaker, Sir, while it is our policy to moderate the tax rates and simplify procedures, the government is equally committed to curb evasion of taxes. It is reported that in some sectors, like induction furnace, steel re-rolling mills etc., evasion of excise duty is substantial and the production is not being reported correctly. I propose to tackle this problem by introducing collection of excise duty on the basis of their production capacity. Suitable legislative changes in the excise law for enabling the implementation of the aforesaid change are under consideration. The details of the proposals would be submitted to this House in due course.

145. The average citizen consumes a basket of commodities. As a result of my proposals — some increases and many reductions — I believe the basket will carry a significantly lower tax burden.

146. The services sector contributes nearly 40% to the GDP. 'Services' are products as much as 'manufactured goods'. Both must bear taxes. Hence, I propose to extend the service tax to cover a number of well known services like:

- Transportation of goods by road;
- Consulting engineers;
- Custom house, Steamer and Clearing and Forwarding agents;
- Air travel agents, tour operators and car rental agencies;
- Out-door caterers, pandal contractors and mandap keepers;
- Man-power recruitment agencies.

147. The proposals on service tax are estimated to yield a revenue of Rs.1200 crore in a full year. However, for the financial year 1997-98, I am taking credit for Rs.900 crore. I wish to inform the House that in order to improve our national highways, I propose to utilise the bulk of the proceeds realised from service tax on transportation of goods by road to augment the resources of the National Highway Authority.

148. On the conventional basis, my proposals relating to reduction in customs duties are estimated to result in a loss of Rs.2625 crore in a financial year and, in the case of excise duties, my proposals are broadly revenue neutral. However, the buoyancy and the growth momentum that would be imparted to the economy would more than compensate for our losses computed through the conventional calculations.

149. I now have to say something on behalf of my colleague the Minister of Communications who has made a statement earlier today. A revision of tariffs for some postal services has become unavoidable. However, in doing so, we have kept in view the interest of the common man and the role of postal services in meeting wider social obligations. While there is no change for Registered Newspapers, the price for ordinary Post Card is being raised to 25 paise and printed Post Card to Rs.1.50. The price for Inland Letter is also being raised from 75 paise to Re.1 and for Envelope from Re.1 to Rs.2. Certain other changes are also being effected which is explained in the Memorandum circulated alongwith the budget documents. The changes will take effect from a date to be notified later. The proposed revisions are estimated to yield an additional revenue of Rs.367 crore in a full year and Rs.305 crore during 1997-98. This modest increase is necessary for the development of postal services and in partially bridging the deficit on the numerous services being provided by the Postal Department.

150. Copies of notifications giving effect to the above changes in customs and excise duties will be laid on the Table of the House in due course.

151. Mr. Speaker, Sir, as I come to the end of my labours, let me look at the final outcome. The revenue deficit in 1997-98 is placed at Rs.30,266 crore or 2.1% of GDP. The fiscal deficit comes

to Rs. 65,454 crore which is 4.5% of GDP. I have not wavered in my commitment to continue on the course of fiscal correction. With the support of this House, and as promised in the CMP, I hope to bring the fiscal deficit under 4% in the next budget.

152. Our goal must be to achieve rapid and broad-based growth which alone can ensure higher employment, better living standards and a humane and just society. The challenges that we face today are not unique to India. Other countries, including our friends in Asia, have faced similar challenges. Japan showed the way. Other Asian countries are surging ahead. And, finally, there is the example of China, powering its way to becoming the second largest economy in the world. These countries have shown that with courage, wisdom and pragmatism they can find their rightful places in the world.

153. Deng Xiao Peng, to whom we paid homage a few days ago, once said, "From our experience of these last few years, it is entirely possible for economic development to reach a new stage every few years. Development is the only hard truth." India's economy has also reached a new stage. Our beloved India is far stronger today than she was six years ago.

154. I would appeal to this House, and to the Indian people, to heed the call of Gurudev Rabindranath Tagore:

*Desha desha mandita kart mandrita tabha bheri
Aashulo jata bhabhuta aashana tabha gheri
Deen aagata oyi, Bharat tabu kai?
Shay ki rahila lupta aaji shaba-jana-paschatay?
Lok bishwakarmabhar mill shabar shathay*

(Thy call has sped over all countries of the world
And men have gathered around thy seat.
The day is come; but where is India?
Does she still remain hidden, lagging behind?
Let her take up her burden and march with all.)

155. Mr. Speaker, Sir, with these words, I commend the Budget to this august House.

J. S. MATHUR

Addl. Secy. (Budget)

